

हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कराने के लिए स्पीकर के ओएसडी सुप्रीम कोर्ट जायेंगे?

दूसरी ओर, एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका दर्ज कराने वाले प्रार्थी शेखर मेवाड़ा व कैलाश राम ने सुप्रीम कोर्ट में “केविएट” फाइल की, 5 अगस्त को इस मामले में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6, अगस्ता। एक अहम घटनाक्रम में, अब तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट और न्यायाधीश समीर जैन ने 4 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था।

इससे भी ज्यादा चौंकाते और स्तब्ध कर देने वाली बात यह है कि राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव शर्मा को ओम बिड़ला ने दिल्ली बुलाया था, जहां उन्होंने बिड़ला और राजीव दत्ता, दोनों से मुलाकात की।

संभवतः यह पहला अवसर है, जब किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उस आरोपी से मुलाकात की है, जिसके

- जैसा कि विदित ही है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश समीर जैन ने, लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ ‘ह्यूमन ट्रेफिकिंग’ के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश चार अगस्त को पारित किये थे।
- अजीबोगरीब बात यह भी है कि कांग्रेस ने भी किन्हीं कारणों से इस प्रकरण में चुप्पी साधने का निर्णय सा ले लिया है। क्योंकि, जब किसी कनिष्ठ कर्मचारी ने इस मामले की खबर, पीसीसी की वैंबसाइट पर डाली तो तुरन्त आदेश आ गया, पार्टी के उच्चतम स्तर से, कि प्रकरण की स्टोरी वैंबसाइट पर नहीं दिखाई जाए।

खिलाफ राज्य के हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया हो।

हालांकि मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, यह केवल कयास ही है, लेकिन पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों में इस बात को लेकर

खासी चर्चा और उत्सुकता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने डीजीपी को क्या निर्देश दिए होंगे।

सूत्रों के अनुसार, कथित रूप से मानव तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे राजीव दत्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि

हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के आदेश को रद्द कराया जा सके। इसके लिए वे एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं, शेखर मेवाड़ा और कैलाश राम ने, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए तथा गड़बड़ी की आशंका के कारण पहले ही, 5 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है, ताकि बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला न हो सके।

राजस्थान और दिल्ली की सत्ता के गलियारों में दत्ता के इस मामले को लेकर काफी चर्चा और दिलचस्पी देखी-सुनी जा रही है।

दिलचस्प बात यह है कि किसी भी कांग्रेस नेता ने अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया

नयी दिल्ली, 06 अगस्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत यहां बने केन्द्रीय सचिवालय भवनों में से एक कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उनके साथ केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल भी थे। इस दौरान मोदी ने कर्तव्य भवन का दौरा किया और यहां बनायी गयी सभी सुविधाओं का निरीक्षण

- 50 हजार वर्ग मीटर में फैला यह भवन पूर्णतया ईकोफ्रेंडली है, और कई प्रमुख मंत्रालयों के कार्यालय इसी भवन में बनाए जाएंगे।

भी किया।

यह लगभग एक लाख 50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर है, जिसमें दो बेसमेंट और सात तल (भूतल 6 तल) हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय विभाग और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष ने संसदीय गतिरोध खत्म करने का समाधान दिया सरकार को

विपक्षी दलों ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के बजाय चुनाव सुधार पर चर्चा करवाने की पेशकश की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 अगस्ता। एक रचनात्मक पहल करते हुए, विपक्ष ने कथित रूप से पीठासीन अधिकारी और सत्तापक्ष को “मध्य मार्ग” के रूप में एक सुझाव दिया है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव सिविज्ज/एस.आई.आर.) पर बहस की मांग को लेकर संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए “चुनावी सुधारों” पर चर्चा कराई जाए।

हालाँकि, सरकार ने इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विपक्षी दलों के सूत्रों का कहना है कि सरकार इस तरह की किसी भी बहस को अनुमति देने के मूड में नहीं है।

बुधवार को लोकसभा में

- लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि संसद में किन-किन वर्षों में चुनाव सुधार पर चर्चा हुई है।
- केन्द्र सरकार ने विपक्ष के प्रस्ताव पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विपक्षी दलों के सूत्रों ने कहा कि ऐसा लगता है, सरकार चुनाव सुधार पर चर्चा कराने की इच्छुक भी नहीं है।

एस.आई.आर. पर चर्चा की मांग के दौरान केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा के नियम विचाराधीन (सब- जूडिस) मामलों पर चर्चा की अनुमति नहीं देते। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्थाओं के कामकाज पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती।

इस बीच, कांग्रेस महासचिव

(संचार) जयराम रमेश ने लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई की एक पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया कि संसद में चुनावी सुधारों और चुनाव आयोग के कामकाज पर चर्चा का एक लंबा इतिहास रहा है।

रमेश ने कहा कि गोगोई ने गहन शोध किया है और “मोदी सरकार के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कैलाश मानसरोवर यात्रा रोकी गई

नैनीताल, 06 अगस्ता। उत्तराखंड के कुमाऊं में बादल फटने का कहर फिलहाल बुधवार शाम को थम गया, लेकिन उसका असर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पड़ा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा बुधवार को धारचूला से आगे नहीं बढ़ पाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैलाश मानसरोवर यात्रा का 48 सदस्यीय चौथा दल मंगलवार को

- उत्तराखंड में आई आपदा की वजह से यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई है।

पिथौरागढ़ के धारचूला पहुंच गया था। रात्रि विश्राम के बाद, आज दल को उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित पहले आधार शिविर गुंजी पहुंचना था, लेकिन अतिवृष्टि के चलते भूस्खलन होने से धारचूला-लिपुलेख मार्ग कई जगह अवरुद्ध हो गया।

एस.सी.ओ. सम्मेलन में प्र.मंत्री मोदी जायेंगे इस माह भारत की कूटनीति के लिए यह परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि भारत ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहता, कि दोनों “सुपर पावर” ग्रुप में से एक-एक का चयन करना पड़े उसे

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 अगस्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने के अंत में चीन जा रहे हैं, जहाँ वे शंघाई कोऑपेरेशन आर्गनाइजेशन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ रहा है और भारत प्रमुख शक्तियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता के बीच फंसा हुआ है। इस यात्रा की पृष्ठभूमि विशेष रूप से जटिल है, अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाते हुए भारत पर भारी शुल्क लगाए हैं, साथ ही भारत पर रूस से तेल आयात कम करने का दबाव भी बना रहे हैं, जबकि रूस, भारत का लंबे समय से रणनीतिक

साझेदार रहा है। इन घटनाओं ने भारत की कूटनीतिक गुंजाइश को सीमित कर दिया है, जिससे नई दिल्ली के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में विविधता लाना आवश्यक हो गया है। इस पृष्ठभूमि में, मोदी की चीन पहल को एक रणनीतिक पुनर्संतुलन के रूप में देखा जा रहा है, एक ऐसा कूटनीतिक दांव, जो अमेरिकी दबाव को कम करने में सहायक हो सकता है। भारत भले ही वॉशिंगटन के साथ अपने संबंधों के प्रति प्रतिबद्ध हो, विशेषकर प्रौद्योगिकी, रक्षा और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा ढांचे में, लेकिन बीजिंग के साथ नए सिरे से संवाद ऐसे अधिक संतुलित विदेश नीति का संकेत देता है, जो रणनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत

- भारत, अमेरिका के साथ टैकनॉलजी, डिफेंस सहयोग तो चाहता है, पर, क्षेत्रीय मामलों में अपने हितों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता की इच्छा भी रखता है।
- साथ ही पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किये गये नरसंहार वाकिया भी ताज़ा है, भारत के दिलो-दिमाग पर। अतः, चीन द्वारा पाकिस्तान का पक्ष लेना हर मामले में, चाहे वह मामला आतंकवादी गतिविधियों के बारे में ही क्यों न हो, भारत के लिए पीड़ादायक अहसास है।
- एस.सी.ओ. सम्मेलन में वॉशिंगटन, मॉस्को व बीजिंग के बीच कैसे संतुलन बैठाकर आगे बढ़ा जाए, यह भारत के लिए वाकई में चुनौती है।
- चर्चा है कि सम्मेलन के दौरान प्र.मंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन व चीन के प्रेंसिडेंट शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं।

प्रतिद्वंद्वी वैश्विक शक्तियों के बीच किसी एक पक्ष का चयन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

हालांकि, यह संवाद कई

जटिलताओं से भरा हुआ है। यह यात्रा उस समय हो रही है, जब कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले में कई भारतीय सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की जान चली गई। इस घटना ने पाकिस्तान के प्रति चीन के रुख को लेकर भारत की चिंताओं को फिर से उभार दिया है, विशेष रूप से इस बात

को लेकर कि चीन अब भी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने से हिचकता है। बीजिंग का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे वैश्विक मंचों पर बार-बार पाकिस्तान का बचाव करना, भारत और चीन के बीच तनाव का प्रमुख कारण रहा है।

ऐसे में, चीन के शीष नेतृत्व के साथ भारत की उच्चस्तरीय बैठकें केवल आर्थिक या सीमा-सम्बंधी कूटनीति तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि यह दोनों देशों के परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन साधने की एक चुनौतीपूर्ण कवायद होगी। क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को आर्थिक साझेदारी और एशिया में रणनीतिक प्रभाव बनाए रखने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने भारत पर रूस से “ऑयल” खरीदने के एवज़ में 25 प्रतिशत टैरिफ और लगाया

अमेरिका ने ऐसी पैनल्टी चीन पर लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई, हालांकि, चीन भी भारी मात्रा में रूस से “ऑयल” खरीदता है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
वॉशिंगटन, 6, अगस्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत के निर्यात पर आज 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ (शुल्क) लागू कर दी है, जिसकी उन्होंने पहले ही धमकी दी थी। यह नया टैरिफ पहले से लगे 25 प्रतिशत के “पैसिप्रोकल टैरिफ” (प्रतिशोधी शुल्क) के ऊपर जोड़ा जाएगा, जिससे कुल शुल्क अगले 21 दिनों में 50 प्रतिशत हो जाएगा।

इस नए कदम के साथ ही, ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर पहला “सेकन्डरी सैंक्शन” लगा दिया है, जबकि रूस के तेल के दूसरे बड़े खरीदार चीन पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

इस संयुक्त शुल्क से भारत एक विशेष स्थिति में आ जाएगा, जिसमें उस पर अमेरिका का सबसे ऊंचा 50 प्रतिशत शुल्क लगेगा। इसका सीधा असर यह हो सकता है कि भारतीय निर्यात पूरी तरह से अमेरिकी बाजार से बाहर हो जाए, क्योंकि कीमतें बहुत

- इस बड़े हुए टैरिफ के कारण भारतीय माल अमेरिका के बाजारों से लुप्त ही हो जाएगा तथा भारत को अन्य मार्केट ढूंढ़ने पड़ेंगे, अपना माल बेचने के लिए।
- पर, रूस के अलावा अन्य स्रोतों से ऑयल खरीदने का विकल्प नहीं बचा है भारत के समक्ष। क्योंकि, अन्य स्रोतों से ऑयल की खरीद बहुत महँगी पड़ेगी भारत को।
- भारत का अमेरिका को निर्यात बहुत कम है तथा निर्यात बंद होने से इतना नुकसान नहीं होगा, जितना “ओपन मार्केट” से ऑयल खरीदने से होगा।
- चीन पर पैनल्टी नहीं लगाने से ट्रंप की “टी.ए.सी.ओ.” (ट्रंप आलवेज़ चिकन्स आउट) की छवि को और स्पष्ट और मजबूत कर देता है।

बढ़ जाएगा।

ट्रंप ने यह घोषणा ऐसे समय में की है, जब अमेरिका की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत चल रही है। ट्रंप रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वे जल्दी से यूक्रेन में अपना युद्ध समाप्त करें।

चाहे अनचाहे, इस कदम ने भारत

को अमेरिका और रूस जैसी प्रतिद्वंद्वी महाशक्तियों के बीच चल रही भू-राजनीतिक खींचतान के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है, जो यूक्रेन युद्ध को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ रणनीतिक दांव-पेंच खेल रहे हैं। भारत ने ट्रंप की भारतीय निर्यात पर सेकन्डरी प्रतिबंध

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उत्तरकाशी आपदा में 100 से अधिक के मरने की आशंका

आधी रात के बाद बादल फटने से आई बाढ़ से भारी विनाश हुआ कई गांव शेष दुनिया से कट गए हैं

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 अगस्ता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली कस्बे के पास सोमवार देर रात बादल फटने से आई भीषण बाढ़ में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। इस आपदा ने भारी तबाही मचाई है, कई इलाके पूरी तरह से कट गए हैं, क्योंकि सड़कों के ध्वस्त हो जाने, पुलों के टूटने और संचार लाइनों के बाधित होने से संपर्क टूट गया है।

आपदा के 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद, राहत एवं बचाव कार्यों में गंभीर अड़चन बनी हुई है। राहत कार्यों में प्रशासन के सहयोग के लिए भारतीय सेना को तैनात किया गया है, लेकिन दुर्गम इलाकों तक पहुंच अब भी सीमित है। जमीनी रिपोर्टों के अनुसार, महत्वपूर्ण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, राजमार्ग के कम से कम तीन बड़े

- गंगोत्री नेशनल हाईवे को भारी नुकसान हुआ है। धराली से 40 किलोमीटर दूर भटवाड़ी के पास ही बैरिकेड लगाकर हाईवे को बंद कर दिया गया है।
- राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए विमानों से राहत सामग्री गिराई, क्योंकि खराब मौसम और भारी विनाश के कारण राहत व बचाव दल आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

हिस्से धंस चुके हैं या टूट चुके हैं, जबकि कई अन्य हिस्से भूस्खलन के कारण बह गए हैं। फिलहाल यह हाईवे धराली से लगभग 40 किलोमीटर पहले भटवाड़ी के पास बैरिकेड लगा दिए गए हैं।

क्षेत्र में बिजली आपूर्ति, मोबाइल नेटवर्क और अन्य आवश्यक सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इनकी बहाली के प्रयास जारी हैं, लेकिन भारी तबाही और लगातार खराब मौसम के चलते प्रगति धीमी है। गंगनानी के पास

एक पुल पूरी तरह से बह गया है, जिससे प्रभावित इलाका और अधिक अलग-थलग पड़ गया है

राज्य सरकार ने हवाई राहत अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हेलीकॉप्टरों से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए और प्रभावित लोगों के लिये आवश्यक सामग्री गिरायी जा रही है। मलबे से एक और शव मिलने के बाद, अब तक आधिकारिक तौर पर केवल पाँच मौतों की पुष्टि हुई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और निवासियों को आशंका है

कि मौतों का वास्तविक आंकड़ा कहीं अधिक हो सकता है। जमीन पर काम कर रही राहत टीमें मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रही हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, नुकसान का जायज़ा लिया और पूर्ण सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, हर एक जीवन कीमती है और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी हालात का जायज़ा लिया और मुख्यमंत्री धामी से सीधे बात कर संकटपूर्ण स्थिति की जानकारी और सरकारी प्रयासों और उपायों के बारे में अपडेट लिया।

धराली तक वैकल्पिक मार्ग खोलने के प्रयास जारी हैं, लेकिन सड़क

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक अक्टूबर से बहाल होंगी एयर इंडिया की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

नई दिल्ली, 06 अगस्ता। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया के विमानों का परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, हालांकि अब

- अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सुरक्षा जांच लंबित होने की वजह से एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय सेवा पर आंशिक रोक लगा दी गई थी।

धीरे-धीरे एयर इंडिया के विमानों की आवाजाही सामान्य होती जा रही है। इस बीच बुधवार को एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के सीईओ कैप्टेन विल्सन ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उपीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

शहरों की बिगड़ती आबोहवा, नागरिकों का स्वास्थ्य ख़तरे में

राजस्थान एक गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। वायु, जल, ध्वनि और औद्योगिक प्रदूषण के साथ-साथ खनन से उत्पन्न धूल ने न केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता को प्रभावित किया है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर भी गहरा असर डाला है। शहरों की बिगड़ती आबोहवा ने सांस लेने में तकलीफ, बीमारियों में वृद्धि और पर्यावरणीय असंतुलन का गम्भीर संकट खड़ा कर दिया है। आज यह संकट केवल बड़े शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदूषण का प्रभाव तेजी से फैल रहा है। राजस्थान के शहरों में वायु, जल, ध्वनि, औद्योगिक और खनन से संबंधित प्रदूषणों के कारण स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आज वायु प्रदूषण राजस्थान के शहरों में एक गंभीर समस्या बन चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, श्रीगंगानगर, जयपुर, दौसा, कोटा और भिवाड़ी जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब और बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अप्रैल 2०25 में श्रीगंगानगर में एक्यूआई 321 तक पहुंच गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों से कई गुना अधिक है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में वाहनों की बढ़ती संख्या, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियाँ और खनन से उत्पन्न धूल शामिल हैं। जयपुर, जो पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है, में यातायात का दबाव और सड़कों पर उड़ने वाली धूल के कारण पीएम 1० और पीएम 2.5 जैसे महीन कणों की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। ये कण फेफड़ों में प्रवेश कर श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे अस्थमा, ब्रॉन्काइटिस और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) को बढ़ावा दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से भिवाड़ी, अलवर और कोटा में, कारखानों से निकलने वाला धुआं और रसायन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के एक अध्ययन के अनुसार, राजस्थान के शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन जैसे गैसीय प्रदूषकों का स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे एक बहु-प्रदूषक संकट उभर रहा है। भिवाड़ी, जो एक औद्योगिक हब के रूप में जाना जाता है, में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत गैर-प्राप्ति वाले शहरों में शामिल है। राजस्थान के छोटे शहरों और कस्बों में भी वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट देखी जा रही है, जो पहले केवल बड़े शहरों तक सीमित थी। निर्माण गतिविधियाँ, सड़कों की मरम्मत और बुनियादी ढांचे के विकास ने भी धूल प्रदूषण के स्तर को की गुना बढ़ा दिया है। विशेष रूप से शुष्क जलवायु और तेज हवाओं के कारण धूल के कण हवा में लंबे समय तक रहते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता और खराब होती है।

वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह पर्यावरणीय संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। इसके अलावा, वायु प्रदूषण ने पर्यटन उद्योग पर भी असर डाला है। उदयपुर की प्रसिद्ध झीलें, जो कभी अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए जानी जाती थीं, अब प्रदूषण के कारण अपनी चमक खोती जा रही हैं। राजस्थान सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसके कारण इसे किसी न किसी रूप से विफल माना ही जाएगा। राज्य में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर, विशेष रूप से हनुमानगढ़, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और धौलपुर जैसे जिलों में, जहां 3०0 से ऊपर पहुंच गया है, गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है। औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का धुआं, और पराली जलाना प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (‘सॅड’) के तहत कदम उठाए हैं, जैसे पराली जलाने पर रोक और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना, लेकिन इनका प्रभाव बहुत सीमित रहा है।प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की निगरानी में कमी, औद्योगिक इकाइयों पर सख्ती का अभाव, और पुराने वाहनों पर नियंत्रण की कमी ने समस्या को और गंभीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान सहित अन्य राज्यों से प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर जवाब मांगा है। यह सरकार की निष्क्रियता को तो दर्शाता ही है जनजागरूकता और स्थानीय निकायों के सहयोग की कमी भी एक बड़ी बाधा है। हालांकि, हाल के प्रयासों में राजस्थान पुलिस को पराली जलाने पर निगरानी के लिए अनाज्ञत किया गया है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए और सख्त नीतियों, नियमित निगरानी, और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देना आवश्यक है।

इसी जल प्रदूषण राजस्थान में एक और गंभीर चुनौती है। राज्य में जल संसाधनों की कमी पहले से ही एक बड़ी समस्या है, और उस पर जल प्रदूषण ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सोबेज और कृषि अपवाह ने नदियों, झीलों और भूजल को दूषित कर दिया है। जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक कचरे के कारण कई गांवों में पानी की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। एक टवीट में जोधपुर के अराबा, डोली और धवा जैसे गांवों में फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक कचरे के प्रभाव का जिक्र किया गया, जहां पानी इतना दूषित हो चुका है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। राज्य की प्रमुख नदियों, जैसे चंबल और बना, में औद्योगिक और घरेलू कचरे का अंधाधुंध निपटान हो रहा है। कोटा और बूंदी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, जिसमें भारी धातुएं जैसे सीसा, कैडमियम और आर्सेनिक शामिल हैं, नदियों में छोड़ दिया जाता है। ये धातुएं जलीय जीवन को नष्ट करने के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल रही हैं। खतरनाक कचरा अधिकांशतः नदियों और जलाशयों में बहा दिया जाता है जो राजस्थान के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि यहां जल संसाधनों की कमी के कारण लोग पहले से ही सीमित जल स्रोतों पर निर्भर हैं।

आशा की जानी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी वाले प्रकरण में दिए गए निर्णय की भावना को समझते हुए अनावश्यक रूप से एफआईआर दर्ज करने का जो सिलसिला कई राज्यों में प्रारंभ हुआ है, उस पर रोक लगेगी।

पाई गई है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण भूजल में धूल और रासायनिक अवशेषों का मिश्रण हो रहा है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में अनुपचारित सोबेज का रिसाव भूजल को और दूषित कर रहा है। यह स्थिति न केवल पीने के पानी की कमी को बढ़ा रही है, बल्कि जलजनित बीमारियों जैसे डायरिया, हैजा और टाइफाइड के मामलों में भी वृद्धि कर रही है। उदयपुर की फतेहसागर और रंगमण्डा झीलें, जो कभी शहर की शान थीं, अब सीढ़ीज और औद्योगिक कचरे के कारण दूषित हो रही हैं। ध्वनि प्रदूषण के मामलों में तो राजस्थान के शहरों में खतरा और भी तेजी से उभरा है। जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों में वाहनों, कारखानों, लाउडस्पीकरों और निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न शोर ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। विशेष रूप से त्योहारों और सामाजिक आयोजनों के दौरान लाउडस्पीकरों और पटाखों का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को और बढ़ाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण मशीनों और विस्फोटों की आवाज ने शांत वातावरण को नष्ट कर दिया है। खनन गतिविधियां राजस्थान में प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत हैं। राज्य में मार्बल, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और अन्य खनिजों का बड़े पैमाने पर खनन होता है, जिससे धूल और मसबवे का उत्सर्जन होता है। उदयपुर, मकाना और राजमर्ग जैसे क्षेत्रों में खनन से उत्पन्न धूल ने हवा और पानी दोनों को दूषित किया है। यह धूल न केवल वायु प्रदूषण को बढ़ाती है, बल्कि फसलों और मिट्टी की उर्वरता को भी प्रभावित करती है। खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियां आम हो गई हैं, जो सिलिका धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती है। इसके अलावा, खनन से उत्पन्न मसबवा नदियों और जलाशयों में बह जाता है, जिससे जल प्रदूषण और बाढ़ का खतरा बढ़ता है।

औद्योगिक प्रदूषण भी राजस्थान के पर्यावरण को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भिवाड़ी, अलवर, कोटा और जोधपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों से निकलने वाला धुआं और रासायनिक कचरा न केवल हवा और पानी को दूषित कर रहा है, बल्कि मिट्टी को भी प्रभावित कर रहा है। ध्वनि प्रदूषण में टेक्सटाइल उद्योगों से निकलने वाला रंगीन अपशिष्ट जल नदियों और भूजल में मिल रहा है, जिससे आसपास के गांवों में पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। कचरे का प्रबंधन तो एक बड़ी चुनौती है ही। शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे का ढेर और उसका अנוचित निपटान पर्यावरण को और अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। जयपुर और कोटा जैसे शहरों में कचरे के ढेर खुले में जलाए जाते हैं, जिससे धूल में जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन होता है। प्रदूषण का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी असर डाल रहा है। प्रदूषित हवा और पानी के कारण स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हुई है, जिससे चिकित्सा खर्च बढ़ा है। सिलिकोसिस, कैंसर, खदब रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, प्रदूषण ने पर्यटन उद्योग को भी प्रभावित किया है।

हालांकि प्रदूषण की इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत राजस्थान के कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वच्छ ईंधन, जैसे सीएनजी और एलपीजी, को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम स्थापित किए गए हैं, और कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। लेकिन इन नियमों का अनुपालन और कार्यान्वयन अभी भी अपर्याप्त है। जल प्रदूषण को कम करने के लिए, सरकार ने नदियों और जलाशयों की सफाई के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। चंबल नदी की सफाई के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन औद्योगिक अपशिष्ट और सोबेज के निरंतर निर्वहन ने इन प्रयासों को प्रभावित किया है। भूजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग और बाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को स्थापना पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, कुछ शहरों में लाउडस्पीकरों और वाहनों के हॉर्न पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इन नियमों का पालन कम ही देखा जाता है। खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने कुछ क्षेत्रों में अवैध खनन पर रोक लगाने की कोशिश की है, लेकिन भ्रष्टाचार और स्वच्छताही के कारण यह समस्या बनी हुई है। कचरे के प्रबंधन के लिए, कुछ शहरों में रोसाइक्लिंग और कम्पोस्टिंग सुविधाएं शुरू की गई हैं, लेकिन ये प्रयास अभी प्रारंभिक चरण में हैं।

प्रदूषण की इस जटिल समस्या से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार, उद्योगों, स्थानीय समुदायों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना, औद्योगिक अपशिष्ट के लिए सख्त नियम लागू करना, और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर, समुदाय आधारित निगरानी और स्वच्छता अभियान भी प्रभावी हो सकते हैं। राजस्थान की बिगड़ती आबोहवा एक चेतावनी है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट और गहरा सकता है। यह न केवल पर्यावरणीय, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी आपदा का रूप ले सकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि राजस्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को बरकरार रख सके। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे। सामूहिक प्रयासों से ही इस संकट से निपटा जा सकता है, और राजस्थान को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है।

—अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र मोहन शर्मा वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद् और चिन्तक

“वोकल फॉर लोकल” के आह्वान को राज्य सरकार ने आत्मसात किया

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) विशेष.....



हेमन्त सिंह

देश के इतिहास के पन्नों में 7 अगस्त, 19०5 को स्वदेशी आंदोलन के रूप में एक नया अध्याय जुड़ा था, इस दिन कोलकाता के टाउन हाल से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का शंखनाद हुआ था। स्वदेशी को स्वाभिमान से जोड़ने वाले इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष

2०15 में इसे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (नेशनल हैण्डलूम डे) के रूप में मनाने की पहल की।

स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और खासकर हथकरघा को एक नई चेतना दी। वैसी ही स्वत्व एवं गर्व की छवि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के विजन में भी झलकती है और यह मंत्र अब भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का परिचायक भी बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के इस ‘वोकल फॉर लोकल’ के आह्वान को आत्मसात किया और अपनी ठोस नीतियों के माध्यम से इसे राजस्थान में नई बनावट दी।

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कोटा डोरिया की महीनता से लेकर सांगानेर और अजरक प्रिंट तक की परम्परागत कला ने न केवल समृद्ध संस्कृति और सभ्यता का तराना रचा है बल्कि वस्त्र उद्योग के रुप में आज भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ताना बाना बुन रही

- ‘स्वदेशी’ से ‘आत्मनिर्भरता’ तक कालजयी है हमारी विरासत राजस्थान में ‘वोकल फॉर लोकल’ की नई बुनावट है पंच गौरव कार्यक्रम

है। कोटा डोरिया और सांगानेर प्रिंट ने देश की सीमाओं से परे अन्तर्राष्ट्रीय फैशन इंडस्ट्री में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल उद्योग के नये केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ‘राजस्थान टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2०25’ लागू की है।

इसके अंतर्गत हैण्डलूम जैसे ट्रेडिशन को भी को नवीनतम तकनीक से जोड़ने के लिए पर्याप्त और आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, राज्य सरकार ने कोटा, बालोतरा, भीलवाड़ा, पाली के वस्त्र कला के उत्पादों को पंच गौरव जैसे कार्यक्रम का भी हिस्सा बनाया है।

पंच गौरव कार्यक्रम से **पनपती स्थानीय पहचान** :– देश

(खेल) इसके उदाहरण है। स्थानीयता एवं विशिष्टता के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन, पहचान एवं विकास की पंचधारा से प्रदेश के सभी अंचलों के स्थानीय तत्व अब देश-विदेश में ‘ब्रांड राजस्थान’ बन रहे हैं।

आज 7 अगस्त का दिन हमें यह याद दिलाता है कि आत्मनिर्भरता हमारे देश के लिए आत्मगौरव का विषय है। वैश्विक परिदृश्य में जब आज अन्य देश टैरिफ नीतियों की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमारी कालजयी विरासत को संजोते हुए स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों को विकल्प की बजाए आवश्यक रूप में अपनाने का मंत्र और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की नीतियाँ इसी दिशा में विकास और विरासत की संतुलित करते हुए एक नए एवं समृद्ध राजस्थान की बुनियाद रख रही हैं।

—हेमन्त सिंह (सहा. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी), मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ,

भारत की पेट्रोलियम कंपनियों का महाविलय: यही समय है! सही समय है!

का एकीकरण हुआ, व्यापारियों से विरोध भी झेलना पड़ा, अफसरों से कड़ा सवाल भी, लेकिन जो एक देश, एक टैक्स, आज हरेक व्यापारी और उपभोक्ता सराह रहा है, वही फायदा पेट्रोलियम में भी मिलेगा।

दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां– भारत को सीखना होगा

दुनिया में सऊदी अरामको जैसी कंपनियां (59० अरब राजस्व, 1.8 ट्रिलियन मार्केट कैप), सिनोपेक–चाइना पेट्रोलियम (487 अरब), पेट्रोचाइना, एक्सॉनमोबिल, शेल जैसे ब्रांड, अपनी भव्य एकीकृत व्यवस्थाओं के बल पर वैश्विक रैंकिंग में टॉप पर हैं। जब हमारी कंपनियों का मार्केट कैपिटललाइजेशन एक साथ होगा, तब भारत भी दुनिया की सूची में कहीं आए बड़ जाएगा।

दुनिया की शीर्ष तेल कंपनियों का राजस्व और मार्केट कैप:–

सऊदी अरामको (Saudi Aramco)
वार्षिक राजस्व: लगभग 59० अरब अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैपिटललाइजेशन: 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर

सिनोपेक (China Petroleum & Chemical)
वार्षिक राजस्व: लगभग 487 अरब अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 58 अरब अमेरिकी डॉलर

पेट्रोचाइना (PetroChina)
वार्षिक राजस्व: लगभग 486 अरब अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 79 अरब अमेरिकी डॉलर

एक्सॉन मोबिल (ExxonMobil)
वार्षिक राजस्व: लगभग 387 अरब अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 445 अरब अमेरिकी डॉलर

शेल पीएलसी (Shell PLC)
वार्षिक राजस्व: लगभग 365 अरब अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 2०2 अरब अमेरिकी डॉलर

भारत की मेगा कंपनी की संभावना
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास 13,772 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी है, इसका मार्केट कैपिटललाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण 2,०9,०65 करोड़ रुपये है और इसके पास कुल रिजर्व्स 1,72,716 करोड़ रुपये हैं। आज की तारीख में इसका शेयर भाव 148 है। कंपनी की सालाना बिक्री 7,58,1०6 करोड़ रुपये तक पहुंचती है

और शुद्ध लाभ 13,789 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।

भारत पेट्रोलियम के पास 4,273 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी है, कंपनी का मार्केट कैप 1,45,665 करोड़ रुपये और रिजर्व्स 77,112 करोड़ रुपये हैं। इसके एक शेयर का दाम अब 336 है। बीपीसीएम ने 4,4०,272 करोड़ रुपये की बिक्री की और 13,337 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास 2,128 करोड़ रुपये की इक्विटी, 9०,475 करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण और 49,०16 करोड़ रिजर्व्स हैं। इस समय बाजार में इसका शेयर 425 है। बिक्री 4,34,1०6 करोड़ रुपये की रही जबकि शुद्ध लाभ 6,736 करोड़ रुपये रहा।

तीनों कंपनियों को जोड़ें तो कुल इक्विटी पूंजी 20,173 करोड़ रुपये, कुल मार्केट कैप 4,45,205 करोड़ रुपये और कुल रिजर्व्स 2,98,844 करोड़ रुपये हो जाते हैं। इनकी कुल बिक्री 16,32,484 करोड़ रुपये हैं और मिलानुला शुद्ध लाभ 33,862 करोड़ रुपये तक पहुंचता है।

यदि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सभी बड़ी भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों मर्ज होकर एक “मेगा इंडिया पेट्रोलियम” कंपनी का रूप लेती है, तो उसके संभावित फायदे और वैश्विक प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे:–

भारत की ‘मेगा कंपनी’ का संयुक्त वार्षिक राजस्व लगभग 200–25० अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है, जिससे वह दुनिया की टॉप-5 तेल कंपनियों की कतार में आ सकती है।

बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) भी बढ़कर लगभग 200–3०0 अरब अमेरिकी डॉलर के लगभग पहुंच सकती है, जिससे भारत वैश्विक मंच पर दिखेगा।

जनाता को पूरे देश में एक ही दर और एक ही क्वालिटी का पेट्रोल–डीजल मिलेगा, जिससे उपभोक्ता प्रीतियां और भ्रष्टाचार दूर होगा।

आज हर राज्य की अपना टैक्स की दरें अलग–अलग होने से उनके बॉर्डर एरिया में जो पेट्रोल पम्प हैं यदि सस्ता है तो बेशुमार बिक्री होती है और अगर बॉर्डर का दूसरा पम्प महंगा है तो उसकी बिक्री नागण्य होती है और इसका उदाहरण राजस्थान –हरियाणा के बॉर्डर पर जा सकता है।

लॉजिस्टिक्स, बफर स्टॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज आदि पर दोहराव खत्म होगा और अनुमानतः 15–2० घनवट से बचा

एक ही क्वालिटी का पेट्रोल–डीजल मिलेगा, जिससे उपभोक्ता प्रीतियां और भ्रष्टाचार दूर होगा।

आज हर राज्य की अपना टैक्स की दरें अलग–अलग होने से उनके बॉर्डर एरिया में जो पेट्रोल पम्प हैं यदि सस्ता है तो बेशुमार बिक्री होती है और अगर बॉर्डर का दूसरा पम्प महंगा है तो उसकी बिक्री नागण्य होती है और इसका उदाहरण राजस्थान –हरियाणा के बॉर्डर पर जा सकता है।

लॉजिस्टिक्स, बफर स्टॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज आदि पर दोहराव खत्म होगा और अनुमानतः 15–2० घनवट से बचा

एक ही क्वालिटी का पेट्रोल–डीजल मिलेगा, जिससे उपभोक्ता प्रीतियां और भ्रष्टाचार दूर होगा।

आज हर राज्य की अपना टैक्स की दरें अलग–अलग होने से उनके बॉर्डर एरिया में जो पेट्रोल पम्प हैं यदि सस्ता है तो बेशुमार बिक्री होती है और अगर बॉर्डर का दूसरा पम्प महंगा है तो उसकी बिक्री नागण्य होती है और इसका उदाहरण राजस्थान –हरियाणा के बॉर्डर पर जा सकता है।

लॉजिस्टिक्स, बफर स्टॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज आदि पर दोहराव खत्म होगा और अनुमानतः 15–2० घनवट से बचा

एक ही क्वालिटी का पेट्रोल–डीजल मिलेगा, जिससे उपभोक्ता प्रीतियां और भ्रष्टाचार दूर होगा।

आज हर राज्य की अपना टैक्स की दरें अलग–अलग होने से उनके बॉर्डर एरिया में जो पेट्रोल पम्प हैं यदि सस्ता है तो बेशुमार बिक्री होती है और अगर बॉर्डर का दूसरा पम्प महंगा है तो उसकी बिक्री नागण्य होती है और इसका उदाहरण राजस्थान –हरियाणा के बॉर्डर पर जा सकता है।

लॉजिस्टिक्स, बफर स्टॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज आदि पर दोहराव खत्म होगा और अनुमानतः 15–2० घनवट से बचा

एक ही क्वालिटी का पेट्रोल–डीजल मिलेगा, जिससे उपभोक्ता प्रीतियां और भ्रष्टाचार दूर होगा।

आज हर राज्य की अपना टैक्स की दरें अलग–अलग होने से उनके बॉर्डर एरिया में जो पेट्रोल पम्प हैं यदि सस्ता है तो बेशुमार बिक्री होती है और अगर बॉर्डर का दूसरा पम्प महंगा है तो उसकी बिक्री नागण्य होती है और इसका उदाहरण राजस्थान –हरियाणा के बॉर्डर पर जा सकता है।

लॉजिस्टिक्स, बफर स्टॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज आदि पर दोहराव खत्म होगा और अनुमानतः 15–2० घनवट से बचा



रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

आज जब भारत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, हमें अपने संसाधनों, व्यवस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में वह क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा, जो अने वाले देशकों में देश को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाए। पेट्रोलियम सेक्टर इसकी सबसे अहम कड़ी है–और यह वही क्षेत्र है जहाँ बिखराव, विभिन्न ब्रांड, गुणवत्ता की खाइयों, डिस्ट्रिब्यूशन में उलझन और बार–बार सामने आती घण्टीयें–चोरियों की खबरें आम हो चुकी हैं।

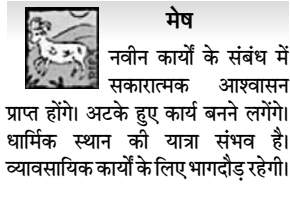
इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कितनी ही सार्वजनिक और निजी कंपनियाँ देश में तेल की आपूर्ति का जिम्मा उठाती हैं। लेकिन क्या ये बिखराव और प्रतिस्पर्धा जनता को वाकई बेहतर सेवा दे पा रही है? हर कंपनी का अपनी कर्पांडीज, अलग–अलग बफर स्टॉक्स, अलग स्टोरेज–ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, अपनी अपनी लॉबी, नेताओं–अफसरों की हिस्सेदारी, पुराना नियम–कायदा, और अंत में पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता में अंतर। क्या कभी आपने सोचा–एक शहर में दो ब्रांड के पंप पर, एक ही दिन एक ही पेट्रोल के दाम–गुणवत्ता अलग कैसे हो सकते हैं?

अब समस्या सिर्फ कीमत या उपभोक्ता के भ्रम की नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की लागत व पारदर्शिता की कमी की भी है। रोजमर्रा के अखबारों की हेडलाइन बनती “पेट्रोल डीजल चोरी”, काला बाजारी, टुक–टैकर घोटाले.. अभी ताजातरीन मामला एक अखबार की फ्रंट पेज पर, पाइप लाइन से क्रूड आयल चोरी को कई दशकों से चल रही है और एक बड़े माफिया का रूप ले चुकी है जो अपने आप में सिस्टम की चाहिए। जीएसटी को ही ले लीजिए, जब इसके लिए 25 से भी ज्यादा विभागों

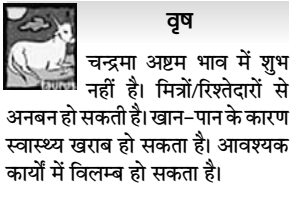
सावन मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत २०८२, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन २:०१ तक, विष्कुम्भ योग प्रातः ६:४२ तक, तैतिल करण दिन २:२८ तक, चन्द्रमा आज रात्रि ८:११ से मकर राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थितिः सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।
आज रविवोग दिन २:०१ से आरम्भ होगा। आज आखेटक त्रयोदशी और शिव पवित्रारोपण है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः शुभ सूर्योदय से ७:३७ तक, चर १०:५४ से १२:३२ तक, लाभ-अमृत १२:३२ से ३:५० तक, शुभ ५:२८ से सूर्यास्त तक।

राहूकालः १:३० से ३:०० तक। सूर्योदय ५:५८, सूर्यास्त ७:०७



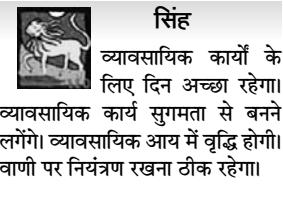
मेघ
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।



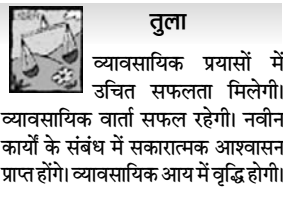
वृष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ बनी नहीं है। मित्रों/रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है। खाने–पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।



मिथुन
परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



सिंह
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।



कन्या
घर–परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक–साम

सार-समाचार

अधिकारी और कार्मिक आपसी समन्वय से करेंगे शिक्षा हित में कार्य

जालोर, (कासं)। शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य एवं समक्ष पदों पर हाल ही में स्थानांतरण हुए हैं। स्थानांतरण के दौरान जिले में विभिन्न पदों पर पदस्थापित अधिकारियों का गुरुवार को जिला मुख्यालय पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से स्वागत बहुमान कर शिक्षा शिक्षण कार्य हेतु चर्चा हुई। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के उपशाखा जालौर अध्यक्ष कृष्णपालसिंह सामूजा ने बताया कि हाल ही में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा लहरीराम माली, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा प्रकाशकुमार दवे तथा अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम ब्लॉक जालौर के पद पर जबरसिंह देवडा का कार्यग्रहण हुआ है इन सभी अधिकारियों का शिक्षक संघ द्वारा अभिनंदन स्वागत किया गया। जिला संरक्षक नारायणसिंह राठौड एवं संभाग संयुक्त मंत्री महिला रेखा राठौड के नेतृत्व में नव पदस्थापित अधिकारियों का स्वागत करते हुए शिक्षा एवं संगठन के कार्य के लिए चर्चा की गई। ब्लॉक कार्यालय में एसबीईओ जबरसिंह देवडा ने साथ मिलकर ब्लॉक में शिखर के नवाचार के लिए कार्य की बात कही और एडीईओ माध्यमिक लहरीराम माली ने कहा कि मैं आपको उपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूंगा। प्रारंभिक शिक्षा के एडीईओ प्रकाशकुमार दवे ने प्रारंभिक शिक्षा में सकारात्मक कार्य की बात कही। इस दौरान जिला सह संगठन मंत्री गणपतसिंह मंडलावत, ब्लॉक महिला मंत्री मीना परमार, ब्लॉक मंत्री मूलाराम प्रजापत, चंचनसिंह चंपावत, मंगलसिंह बालोत, हरीशकुमार, लादूराम, हिम्मतसिंह, कल्पेश बोहरा, बसंतकुमार, सीता ओड, संतोष सोलंकी, महिपालसिंह आनंदसिंह, भूपेंद्रसिंह, कानसिंह, भवर्ष खान, रघुनाथराम सहित जिला महासमिति सदस्य और जिला और ब्लॉक के बडी संख्या में शिक्षक संघ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जन सुरक्षा कैम्प का आयोजन

जालोर, (कासं)। ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने व लाभान्वित करने के उद्देश्य से रानीवाड़ा पंचायत समिति की तावींदर ग्राम पंचायत में जन सुरक्षा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैम्प में जिला अग्रणी बैक, जालोर के मुख्य प्रबंधक रमेश कुमार और सांख्यिकी विभाग, जालोर के उप निदेशक डॉ. धनसिंह राजपुरोहित द्वारा निरीक्षण किया गया। कैम्प में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जन धन खातों में केवाईसी अपडेट, प्रधानमंत्री जन धन खाता, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा तथा अटल पेंशन जैसी विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी के साथ पात्र ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर तावींदर ग्राम पंचायत के प्रशासक कालू सिंह, क्रिसील फाउंडेशन वित्तीय साक्षरता केंद्र सायला के सेंटर मैनेजर भंवर लाल, राजस्थान ग्रामीण बैंक कड़ा के शाखा प्रबंधक सुखविरसिंह, आईसीआईसीआई बैंक के शाखा प्रबंधक अनिल कुमार, बैंक ऑफ इंडिया, शाखा रानीवाडा के सीएएसपी हरीश माली, शैतान सिंह उपस्थित रहे।

स्वच्छता मिशन की बैठक 8 को

जालोर, (कासं)। जल जीवन मिशन के तहत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की 38वीं मासिक बैठक जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में 8 अगस्त, शुक्रवार को प्रत. 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जायेगी। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभिधाता संजय शर्मा ने बताया कि बैठक के दौरान गत बैठक में लिए गए निर्णयों एवं दिशा-निर्देशों, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल की वस्तुस्थिति, नमंदा परियोजना में प्रगतिरत पेयजल योजनाओं, जेजेएम में पूर्ण हुई योजनाओं एवं एसबीएम-जी2 कार्यों की समीक्षा तथा जेजेएम के कार्य पूर्ण होने के उपरांत प्रमाणित पेयजल योजनाओं के संचालन व संधारण के हस्तांतरण एवं सामूहिक व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, नल जल मित्रों के फ्लम्बर ट्रेड हेतु प्रशिक्षण, विद्यालयों व आंगनवाडियों में पेयजल की समीक्षा सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी।

सावन माह में कवड़ यात्रा का आयोजन

बालोतरा, (निसं)। सावन के पवित्र माह में स्थानीय आंगडिया गली कुम्हारों का चौक स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। बुधवार अल सवेरे शिव भक्त,महिलाओं सहित भक्ते कावड़ लेकर मंदिर परिसर पहुँचे।वहां से रवाना होकर छत्रियों का मोर्चा स्थित मरु गंगा लूणी के तट पर पहुँच कर मरु गंगा की पूजा अर्चना कर अपने अपने कावड़ में मरु गंगा का पवित्र पानी भरकर डीजे पर बजते धार्मिक गीतों पर नाचते झूमते हुए पंचायत समिति रोड,पुराना पारु बस स्टैंड, कचहरी रोड,शास्त्री चौक, पुराना बस स्टैंड,द्वितीय रेलवे अंडर ब्रिज,आंगडिया गली होते हुए पुन: नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पहुँच कर सभी कावा?यों का तिलक लगाकर व काव? को तिलक लगाकर मंदिर में प्रवेश करवा कर मंदिर पुजारी जगदीश दास वैष्णव, किशन वैष्णव व रामसुख वैष्णव द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना कर शिवलिंग पर अभिषेक करवाकर कर महा आरती की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया।इस दौरान शिव भक्त ओमप्रकाश प्रजापत, रमेश कुमार वैष्णव, भंवरलाल बागरेका,पूर्व पार्शद नगरज प्रजापत, रावत राम भाटी,भंवरलाल,महेश गुजराती,वेवरचंद, भगवानाराम,सहित सैकडो की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।

‘मां का दूध अमृत के समान’

बालोतरा, (निसं)। राशुकी नाहटा जिला चिकित्सालय शिक्षा विभाग में विश्व स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य में एक विस्तृत जन जागरूकता कार्य म का आयोजन किया गया। इस कार्य म का उद्देश्य नवजात शिशुओं और माताओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्तनपान के महत्व को उजागर करना था।इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप देवात ने उपस्थित माताओं और परिजनों को

संबोधित करते हुए कहा कि माँ का दूध नवजात के लिए अमृत के समान है। यह शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मानसिक विकास में सहायक होता है और उसे कई बीमारियों से बचाता है। उन्होंने माताओं से अपील की कि वे शिशु को कम से कम छह महीने तक केवल स्तनपान कराएँ और उसके बाद पूरक आहार के साथ भी इसे जारी रखें। स्तनपान प्रबंधन इकाई प्रभारी डॉ.

ब्राह्मण जिला सभा बाडमेर के जिलाध्यक्ष निंबाराम जांगिड भियाड ने कहा कि जो घटनाक्रम हुआ वह अत्यंत निंदनीय और पीडादायक है, जिससे न केवल सिर्फ पीडित परिवार बल्कि पूरा समाज आहत है। इस प्रकार की घटनाओं से सामाजिक सौहार्द व आपसी भाईचारे में दरार उत्पन होती है जो कि किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है।बैठक में बताया गया कि वर्तमान में नाबालिग बालिकाओं को बहलाकर ले जाना, ब्लैकमेल करना, उनका शोषण करना जैसी घटनाएं बढ़ रही है।

क्षेत्रों में ऐसे असमाजिक तत्व एक गैंग बनाकर इन नाबालिग बालिकाओं को निशाना बनाते है और उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण करते है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे

कथा से पूर्व कथावाचक के सहायक को साढे छब्बीस लाख रुपये दिये

■ आयोजन समिति के पूर्व सचिव ने कहा कि पैसे नहीं देने का आरोप निराधार

जालोर, (कासं)। जालोर में कथावाचक का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। कथावाचक के जालोर से प्रस्थान करने को लेकर अभी दो दिन रहे हैं। वही 8 अगस्त को भण्डारा के साथ कथावाचक अभयदास को विदाई दी जायेगी।वही कथा के दौरान बार बार आयोजन समिति पर पैसे नहीं देने के आरोप लगाने पर बुधवार को आयोजन समिति के पूर्व सचिव कानाराम परमार व गजेन्द्रसिंह सिसोदिया प्रेस से रुबर हुए । जालोर में कथावाचक द्वारा आयोजन समिति पर मिथ्या आरोप लगाने पर आयोजन समिति के सचिव कानाराम परमार व गजेन्द्रसिंह प्रेस से रुबर होते हुए कहा कि आयोजन समिति ने श्रावण माह में विभिन्न धार्मिक कथा हेतु अभयदास महाराज तखतगढ धाम के द्वारा मुख्य संचालक जोगेश्वर गर्ग की अध्यक्षता में जालोर चातुर्मास का निर्मंत्रण अभयदास महाराज की इच्छा अनुसार स्वीकार किया।जिसमें नगर प्रवेश कलश यात्रा ऐतिहासिक रही।समिति बडे खेद के साथ जालौर

संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव सहन नहीं होगा : मेघवाल

जालोर, (कासं)। आहोर उपखण्ड मुख्यालय पर संविधान बचाओ अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया।इसकेबादे राज्‍यपाल के नाम उपखंड अधिकारी आहोर को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व विधायक व संविधान बचाओ अभियान के जिला समन्वयक पदमाराम मेघवाल ने कहा कि भारत के संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव सहन नहीं किया जाएगा। भारतीय राष्‍ट्रीय काँग्रेस द्वारा निरंतर दबाव के बाद केंद्र सरकार ने एक न्‍या संगत और लोकतांत्रिक जाति आधारित जनगणना की मांग को स्‍वीकार किया। जिलाध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 (5) को तत्‍काल लागू किया जाए।तत्‍कि ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदाय को निजी शैक्षणिक संस्‍थानों में आरक्षण

मिल सके। आहोर विधानसभा प्रल्‍याशी सरोज चौधरी ने कहा कि जाति जनगणना में किसी भी प्रकार की देरी, बहानेबाजी या प्रशासनिक टालम टोल नहीं किया जाना चाहिए और यह प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए, जिसमें संसद में तत्‍काल बहस और पूर्ण बजट प्रावधान शामिल हो। प्रश्‍नावली गणना वर्गीकरण और डाटा प्रकाशन की प्रक्रिया समावेशी और सहभागी होनी चाहिए।

पूर्व प्रल्‍याशी सवाराम पटेल ने कहा कि नवीनमान जाति आंकडों का उपयोग आरक्षण शिक्षा रोजगार और लक्षित कल्‍याण नीतियों की समीक्षा और मजबूती के लिए किया जाए। इस दौरान सभी ने विधानसभा क्षेत्र आहोर के अधिकांश गांव में बिजली, पानी, सडक आदि की समस्याओं के निराकरण के साथ किसानों

जालोर में साहित्यिक परिचर्चा, कलैक्टर ने गुडा बालोतान ग्राम काव्य गोष्ठी आयोजित

जालोर, (कासं)। जिला मुख्यालय स्थित एक निजी होटल में अखिल भारतीय साहित्य परिषद जालोर की ओर से स्वर्णिगीरी का स्वर्णिम इतिहास विषय पर परिचर्चा एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अधिवक्‍त मधुसूदन व्‍यास ने जालोर के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जालौर के इतिहास के कई अनछुए पहलुओं पर कार्य करना बाकी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए निरंतर शोध की आवश्यकता है। लेखक मनोहर सिंह कोटडा ने कहा कि राजस्‍थानी की पहली

पुस्‍तक का लेखन जालौर में ही हुआ था। उन्होंने कहा कि जालौर दुर्ग को युनेस्‍को की विश्व धरोहर की सूची में स्‍थान मिला। चाहिए। अधिवक्‍ता हरिशंकर राजपुरोहित ने दुर्ग के विभिन्न महत्‍वपूर्ण स्‍थलों के बारे में जानकारी प्रदान की। संस्‍कार भारती के प्रांत अध्‍यक्ष जितेंद्र जालोरी ने कहा इतिहास की पुस्‍तकों में जालौर के इतिहास पर बहुत कम लिखा गया है। जालौर का विस्‍तृत इतिहास लेखन अभी बाकी है। उन्होंने विभिन्न लेखकों के द्वारा जालौर के इतिहास पर लिखी महत्‍वपूर्ण पंक्‍तियों को भी पढकर सुनाया।

जालोर, (कासं)। जिला कलक्‍टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने मंगलवार को गुडा बालोतान ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल कर उपस्‍थित ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए उनका मौके पर ही निस्‍तारण किया।

रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलक्‍टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे के समक्ष ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने, विद्युत व पानी की समस्या का समाधान करने सहित विभिन्‍न परिवाद प्रस्‍तुत किए।जनको जिला कलक्‍टर ने गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उनका मौके पर ही निस्‍तारण करने के लिए

जालोर, (कासं)। विद्यालयों में तिरंगा आधा‍रित प्रदर्शनी के माध्‍यम से हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया तथा शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को तिरंगा झण्डे के महत्‍व के बारे में बताते हुए उन्हें अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया।

कुछ समय से क्षेत्र में ऐसे असमाजिक तत्व पनप रहे है जो नाबालिग बालिकाओं को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्‍यपूर्वक अपने जाल में फसाते है, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर शोषण

बोलना उचित समझा,लेकिन वर्तमान में महाराज द्वारा राशि के दुरुपयोग एवं व्‍यवस्‍था के संबंध में आरोप आयोजन समिति पर खुलेआम जनता पर लगाकर जालौर की जनता को भ्रमित कर रहे है। आयोजन समिति के कानाराम मेघवाल ने बताया कि आयोजन समिति ने सर्वसम्‍मति एवं अध्‍यक्ष के निर्देशानुसार राशि का ब्‍यौरा पेश किया जा रहा है। आयोजन समिति द्वारा चातुर्मास आयोजन में 18 जुलाई तक 26,50,000 रुपये का महाराज के मैनेजर विजय राज को भुगतान किया गया । जिसमें टैट व्‍यवस्‍था 13 लाख के विरुद्ध 5 लाख अग्रिम राशि कलश यात्रा के लिए साडी, कलश, नारियल नगर प्रवेश इत्‍यादि राशि का संपूर्ण भुगतान शामिल है।

महाराज की पूरी टीम कौशल्य़ा माता धर्मशाला में निशुल्‍क व्‍यवस्‍था जलंधर नाथ अखाड़े द्वारा की गई ।

महाराज की टीम के भोजन व्‍यवस्‍था के लिए 1 लाख से अधिक किराणे के समान का भुगतान एवं कथा के दौरान विभिन्न व्‍यय महाराज के साफे, फुल, ढोल ढमाके प्रसाद इत्‍यादि सभी आयोजन समिति द्वारा किया जाता रहा है । कुल मिलाकर 18 जुलाई तक आयोजन समिति का 41,70,545 का व्‍यय हुआ है। आज भी आयोजन समिति पर करीब 12 से 13 लाख उधार बाजार में चल रहा है, जिसका भुगतान आयोजन समिति को करना है।आयोजन समिति आज जनता को अवगत कराना चाहती है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की रसीद छपवाकर व्‍यापारी ठेकेदार इत्‍यादि से चंदा इकट्‍ठा नहीं किया गया। आयोजन समिति के सदस्‍यों का व्‍यक्तिगत प्रयास से सहयोग से करीब 30 लाख रुपए शामिल किया गया है । ऐसी स्थिति में महाराज आप आयोजन समिति को दोषारोपित करना सरासर गलत है जालौर में वैमनस्‍य फैलाना कभी उचित नहीं है। आयोजन समिति द्वारा महाराज के साथ समर्पित भावना

ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण

जालोर, (कासं)। जन आधार योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण सहायक विकास अधिकारी किशनलाल प्रजापत की अध्‍यक्षता में पंचायत समिति सांचोर के वीसी रूम में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण में अति. जन आधार योजना अधिकारी एवं ब्लॉक सांख्‍यिकी अधिकारी दिनेश मोघाने ने जन आधार प्रथम स्‍तरीय प्रथम विकास अधिकारियों को जन आधार एप्लीकेशन 2.0 में संशोधन एवं सल्‍यापन करते समय सावधानी बरतने आदि के बारे में जानकारी दी। संगणक हितेश कुमार पुरोहित ने जन आधार 2.0 पोर्टल में किए गए नवीनतम संशोधन एवं प्रक्रियाओं में किए गए सरलीकरण की विस्‍तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में जानकारी दी गई कि सरकारी कार्मिकों के बच्‍चों के नाम आरजीएचए में स्‍वच्‍चालित रूप से जोडे जाएंगे। जन्‍म प्रमाण पत्र के आधार पर स्‍वच्‍चालित रूप से जन आधार में नाम जुड जाएगा और विवाह प्रमाण के आधार पर द्‍वुह्न का

जालोर में साहित्यिक परिचर्चा, कलैक्टर ने गुडा बालोतान ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल की

संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।

रात्रि चौपाल में सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग, जन स्‍वास्‍थ्‍य अभियांत्रिकी विभाग, डिस्‍कॉम व पंचायतीराज सहित विभागीय अधिकारियों ने केन्‍द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्‍न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर, आहोर उपखण्ड अधिकारी सांवरमल रैगर, आहोर तहसीलदार मोहित आशिया सहित ब्लॉक स्‍तरीय अधिकारी व बडी संख्‍या ग्रामीणजन उपस्‍थित रहे।

से कार्य किया। महाराज अपनी अति महत्‍वाकांक्षा के कारण आयोजन समिति को बैक फुट पर आना पडा। आयोजन समिति महाराज के समरसता संकल्‍प के क्रम आग्रह करती है कि चातुर्मास अवधि में आप दो बार जालौर से बाहर गये । चातुर्मास संकल्‍प भंग नहीं हुआ।आपने कथा मंच से आयोजन समिति को बार-बार अपमानित किया क्‍या यह उचित है। आपने अपने वीीडियो में कथा विषय के बारे में प्रशासनिक अधिकारी एवं बडे नेता के प्‍तान में शामिल है। आप उनके नाम का खुलासा कराले है। जालौर जिले के सनातन संतों के बारे में जारी वक्‍तव्‍य किया, वह उचित था। कथावाचक के व्‍यक्ति को दिए गए राशि 26,5०,000 रुपये का खर्च ब्‍यौरा जारी करें। प्रेस वार्ता के दौरान नन्‍दकिशोर जेथलिया, दिलीप सोलंकी,रवि सोलंकी, सुरेश सोलंकी,अशोक गुर्जर,सुरेश सुंदेश, रतन सुथार,दिनेश महावर, भार्गीरथ गर्ग, ओम प्रकाश आंव, जोगाराम मोघा, रमेश मेघवाल,मेथी देवी, मयंक देवडा,

हेमंद्‍रसिंह बग्‍गेडिया, महेश भट्ट, डिम्‍पलसिंह सहित समिति सदस्‍य उपस्‍थित थे। कथावाचक सुबह मांग रहे भिक्षा, शाम को नानी बाई का मायरा, बैनर लगवाने का भुगतान दिलवाने की मांग को लेकर सौपा ज्ञापन – जालोर में कथावाचक अभयदास महाराज भगतसिंह स्‍टेडियम के पास एक भक्‍त के घर से ही नानी बाई का मायरा कथा का वाचन कर रहे है।वही शाम को कथा सुनने वाले लोगो की भीड नजर आ रही है। वही प्रतिदिन सुबह अपने भक्‍तो के साथ भिक्षा लेकर भोजन ग्रहण कर रहे है। वही कथावाचक के भगतसिंह स्‍टेडियम में कथा करवाने को लेकर विज्ञापन व बैनर लगाने वाले विक्रमसिंह ने जिला कलैक्‍टर जालोर को मंगलवार को ज्ञापन सौंपकर विज्ञापन व बैनर लगवाने का भुगतान करवाने की मांग की गई। जालौर में कथावाचक लगातार भगतसिंह स्‍टेडियम के पास नानी बाई का मायरा कथा का वाचन कर रहे है। कथा सुनने के रात्रि तक भक्‍तो की भीड नजर आ रही है।

शैक्षणिक सामग्री का किया वितरण

जालोर, (कासं)। घुमन्तू परिवार के बच्‍चों के लिए संचालित गुरुकुल छात्रावास जालोर में बुधवार को एक प्रेरणादायी कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षणिक सामग्री एवं स्कूल बैग का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन बच्‍चों को शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपल्‍ब्‍ध करवाना और उन्हें आत्‍मानभरंता की ओर अग्रसर करना था। इस पुनीत कार्य में रोटेरियन रमेश जी जैन (तिथी) का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने

व्यक्तिगत सहयोग से सामग्री उपलब्‍ध करवाई।

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
पत्र संं-MB-74-W-0Works/NT दिनांक 05.08.2025 मंडल रेल प्रबन्धक, इजीनियरिंग, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उसकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रगतिरत नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रावजों में निविदा निम्न कार्यों के लिए क्रमानुसार आम्त्रित की जाती है-ई-निविदा सूचना सं. 2025-26 : 82o/2025-26 कार्य का नाम व स्थान : Provision of W Metal Beam Crash Barrier (28000 m) in the section of SSE/PW/Sanddari under ADEN/Sanddari of Jodhpur Division. अनुमानित लागत रूपये : 102415190.94 बयाने की राशि रूपये : 862100.00 ई-निविदा सूचना सं. 2025-26 : 83o/2025-26 कार्य का नाम व स्थान : Provision of W Metal Beam Crash Barrier (20000 m) in the section of SSE/PW/Jalaur under ADEN/Samdari of Jodhpur Division अनुमानित लागत रूपये : 73153707.82 बयाने की राशि रूपये : 515800.00 ई-निविदा सूचना सं. 2025-26 : 84o/2025-26 कार्य का नाम व स्थान : Provision of W Metal Beam Crash Barrier (20000 m) in the section of SSE/PW/Dhanera under ADEN/Samdari of Jodhpur Division अनुमानित लागत रूपये : 73153707.82 बयाने की राशि रूपये : 515800.00 ई-निविदा सूचना सं. 2025-26 : 87o/2025-26 कार्य का नाम व स्थान : Provision of W Metal Beam Crash Barrier (22000 m) in the section of SSE/PW/Balotra under ADEN/Barmer of Jodhpur Division अनुमानित लागत रूपये : 85469078.60 बयाने की राशि रूपये : 552400.00 निविदा सूचना संख्या 82o/2025-26, 83o/2025-26, 84o/2025-26 एवं 87o/2025-26 निविदा प्रस्तुत करने की तिथि 28.08.2025 को 15:00 बजे तक है। वेबसाइट का विवरण जहाँ पर ई-निविदा देखी व भरी जा सकती है – www.ireps.gov.in
87S-CR/25
87S-CR/25

कार्यालय ग्राम पंचायत बादनवाडी पंचायत समिति, जालोर	
क्रमांक/ग्राम/मनेरा/2025-26/227	दिनांक: 05/08/2025
ई-निविदा सूचना संख्या 02/2025-26	
पंचायत समिति जालोर के अधीनस्थ ग्राम पंचायत बादनवाडी के लिए वितरित वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान महात्मा गांधी नरोग योजना एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अन्य योजनाओं में कराये जाने वाले कार्यों के लिए निर्माण सम्पत्ती एवं उपकरणों की आपूर्ति हेतु राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शीता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शीता नियम 2013 (आदिनांक संशोधित) के अनुसार राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के तहत वस्तु एवं सेवाकर (GST) अधिनियम 2017 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत अनुपत्ती एवं इन्सूक बिनिमाता (ओ) / विक्रेता (ओ) / फर्मों /संवेकों) / आपूर्तिकर्ताओं से जो किसी भी राजकीय संस्था / उागमों से बेची गयीने से बिबाईड /ब्लैक लिस्टेड नहीं हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई- प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई-निविद संबंधी समस्त विस्तृत विवरण कार्यालय नोटिस बोर्ड तथा www.eproc.rajjasthan.gov.in एवं www.sppp.rajjasthan.gov.in पर अवलोकन कर काफ़ डबनलौड कर www.eproc.rajjasthan.gov.in ई-निविद ऑनलाईन अपलोड की जा सकती है।	
NIB No. - ZJR2526A0440 UBN No. - ZJR2526GLOB00710	
सरपंच/ प्रशासक	ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बादनवाडी पंचायत समिति जालोर	ग्राम पंचायत बादनवाडी पंचायत समिति जालोर

OFFICE OF THE DY. CONSERVATOR OF FOREST , WILDLIFE, JAISALMER

No:F\J\Store / DCFWL /2025/5476

Date : 04.08.2025

E -NOTICE INVITING TENDER

Bids for RCC Straight post, Chain link fence and Galvanized Barbed wire as per below ENIB Number under Wildlife Division Jaisalmer are invited from interested bidders 04.08.2025 to 13.08.2025 Other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal <https://eproc.rajjasthan.gov.> and <https://sppp.rajjasthan.gov.in> of the state.

NIB Code	UBN No.	Tender ID
FOR2526A0943	FOR2526GLOB01207	2025_FORES_492340_1
FOR2526A0945	FOR2526GLOB01210	2025_FORES_492350_1
FOR2526A0947	FOR2526GLOB01211	2025_FORES_492356_1

Dy.Conservator of Forest

Wildlife Jaisalmer

भय व्याप्त है । सर्व समाज द्वारा ऐसी घटनाओं पर चिंता भी जाहिर की है और आक्रोश भी जाताया है। बैठक में जांगिड पंचायत के अध्यक्ष प्रभुदयाल धीर,जांगिड ब्राह्मण मारवाड सभा के अध्यक्ष हरीश जांगिड मारुडी,जांगिड ब्राह्मण जिला सभा जिलाध्यक्ष निंबाराम जांगिड भियाड, केशराम सुथार धोरीमना, गोपाल सिंह राजपुरोहित, लृणसिंह झाला, हनुमान सैन, प्रो पांचाराम चौधरी, भाखरसिंह सोनदी, रूपसिंह राज्दौड चौहटनर, ममाराम नैण धोरिमना, गणेश बिजाणी, रहीम खान छिपा, बांकाराम जांगिड, नाथूराम जांगिड, नानाराम, गणेश कुमार सहित सैकडों की संख्या में सर्व समाज के अध्‍यक्ष, प्रतिनिधि व गणमान्‍य नागरिक मौजूद रहे।

देवली में एसडीएम ने अपने आवासीय परिसर में लगे हरे-भरे वृक्ष कटवाये

मौके पर मजदूर ने बताया कि उपखंड अधिकारी के आदेश पर हरे वृक्षों की कटाई की जा रही है

देवली, (निर्स)। जहां हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश सहित जिलेभर में वृक्ष प्रेमियों द्वारा और सरकार की ओर से आए दिन पौधारोपण किया जा रहा है, वहीं देवली उपखंड अधिकारी और अधिशासी अधिकारी ने प्रतिबंधित हरे-भरे वृक्षों की बलि ले ली। एक और तो राज्य की भजनलाल सरकार पौधारोपण के साथ-साथ पौधों को वृक्ष बनाने तक के लक्ष्य का संकल्प दिलाव रही है, तो वहीं दूसरी ओर भजनलाल सरकार के ही अधिकारी फल-फूल रहे हरे-भरे वृक्षों को कटवाने की हटधर्मिता अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पौधारोपण करवाने जाने के लिए सरकारी एजेंसियों को लाखों के बजट के साथ पौधारोपण कार्यक्रम करवाकर सफल बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो वहीं इस कार्यक्रम में शामिल आमजन सहित वृक्ष प्रेमियों को इससे प्रेरणा मिलती है। वहीं यह भी बताया जाता है कि वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध दुरुस्त बनाए रखने में कितने महत्वपूर्ण और कितने जरूरी है। परंतु यहाँ नीम, सफेदा और अन्य वृक्षों और पौधों को कटवाया जा रहा है।

देवली उपखंड अधिकारी रूबी अंसार ने अपने आवासीय परिसर में लगे हरे घने वृक्ष नीम, सफेदा इत्यादि



देवली उपखंड अधिकारी आवासीय परिसर में लगे नीम, सफेदा के वृक्ष काट दिये।

किस्म के वृक्षों और पौधों को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के सहयोग से पूरी तरह कटवा दिया यह मामला प्रकाश में आने के बाद जब उपखंड अधिकारी रूबी अनुसार को मीडिया द्वारा यह जानने के लिए फोन किया गया कि उपखंड अधिकारी आवास परिसर बगीचे के हरे-भरे वृक्षों को किस कारण से कटवाया जा रहा है तो इस पर उपखंड अधिकारी ने मीडिया का फोन बार-बार काट कर अड़िग रहते हुए अपनी हटधर्मिता दर्शा दी और परिसर के बगीचे के वृक्ष कटते

चले गए। इस दौरान हरे वृक्षों को काटने वाले मजदूर से जानकारी चाही कि यह हरे वृक्ष क्यों और किसके आदेश पर काटे जा रहे हैं, तो मजदूर महावीर प्रसाद माली ने जानकारी दी कि उपखंड अधिकारी के आदेश पर हरे वृक्षों की कटाई की जा रही है। इसके लिए देवली नगर पालिका ने मजदूरी पर उसे यह कार्य करने के लिए कहा है। मामला यह भी सामने आया कि जिन हरे वृक्षों की कटाई की गई उनके भारी भरकम तनों (लकड़ियों) को मशीनों से काटा गया है। इतना ही

नहीं इस मामले में पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा प्रतिबंधित हरे-भरे वृक्षों की कटाई के मामले पर विशालकाय वृक्षों को काटने की वजह बताते पर अलग-अलग बात कह कर गुमराह करते रहे। उल्लेखनीय है कि गत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान का शुभारंभ किया था। एक और तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने माँ के नाम एक पेड़ लगाने की योजना पर प्रदेशभर में करोड़ों की

■ पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा प्रतिबंधित हरे-भरे वृक्षों की कटाई के मामले पर गुमराह करते रहे

तादाद में पौधारोपण करवाते हुए प्रधानमंत्री की इस योजना को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों भी इस कार्यक्रम के तहत पौधा लगाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन उपखंड अधिकारी आवास परिसर के बगीचे में काटे गए वृक्षों के मामले में किसी भी नेता या उच्च अधिकारी ने वृक्षों की कटाई को रोकने तक का प्रयास नहीं किया, और हरे भरे प्रतिबंध वृक्ष उपखंड अधिकारी की हटधर्मिता पर कटते चले गए। सुरेश कुमार मीणा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका देवली टोंक का कहना है कि उपखंड अधिकारी परिसर के बगीचे में लगे हरे वृक्षों की छंगाई के लिए नगर पालिका की ओर से मजदूर लगाए गए हैं। मजदूरों ने हर वृक्षों को पूरी तरह काट दिया, इस मामले का पता करवाता हूं।

25 लाख की अवैध शराब पकड़ी, दो गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निर्स)। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने लगातार दूसरे दिन गुजरात शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए की शराब की खेप पकड़ी है। पुलिस ने शराब

■ ट्रक के भीतर बनाये गये गुप्त चैबर में शराब भरी मिली

से भरे ट्रक के साथ दो तस्क़र भी गिरफ्तार किए हैं।

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि बीती रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि शराब से भरा ट्रक उदयपुर की तरफ से गुजरात जा रहा है। सूचना पर बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी के नेतृत्व में रतनपुर गुजरात सीमा पर नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी के दौरान चौकी प्रभारी गोविंदसिंह ने हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले एक ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक में बायो मास



बिछीवाड़ा पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध शराब समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

ब्रिक भर हुआ था। वहीं ट्रक के भीतर गुप्त चैबर बनाकर शराब भरी हुई पाई गई। ट्रक चालक से शराब संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वो कोई जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने हिसार हरियाणा

निवासी ट्रक ड्राइवर वीरसिंह और उसके सहयोगी वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ट्रक से शराब को उतरावाकर गिनती की तो ट्रक में 25 लाख रुपए की 3.86 पेटो अंग्रेजी शराब

की पेटियां भरी हुई थी, जो हरियाणा निर्मित थी। पुलिस ने ट्रक सहित अवैध शराब को जप्त कर लिया है। वहीं आबकारी अधिनियम में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

39 टीचर्स के डेपुटेशन रद्द किये

बीकानेर, (निर्स)। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के कुल 39 टीचर्स के डेपुटेशन रद्द कर दिए हैं। ये टीचर्स वेतन तो शिक्षा विभाग से ले रहे थे, लेकिन काम दूसरे विभाग में कर रहे थे। 39 में से 37 टीचर्स तो अलग-अलग जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के ऑफिस में ही वर्ष से जमे हुए थे। वहीं भरतपुर और कोटा कलेक्टर ऑफिस में डेरा डाले दो अध्यापकों को भी वापस विभाग में तलब कर लिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने राज्य सरकार के एक

■ 39 में से 37 टीचर्स तो अलग-अलग जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के ऑफिस में लगे हुये थे

आदेश की पालना में डेपुटेशन रद्द किए हैं। राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का ऑफिस है। इसी ऑफिस में कहीं सीनियर टीचर तो कहीं ग्रेड सैकेंड के टीचर डेपुटेशन पर चल

रहे हैं। अर अल्पसंख्यक मामला विभाग मद्रदासा बोर्ड जयपुर और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में बैठे सभी टीचर्स को हटा दिया गया है। कुछ शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भी खेल मैदान के बजाय इन ऑफिस में काम कर रहे थे। अब इन सभी को यहां से हटाया गया है। कोटा और भरतपुर के जिला कार्यालय में कार्यरत दो टीचर्स की प्रतिनियुक्ति भी निरस्त कर दी गई है। इन सभी को कार्यमुक्त करने के बाद संबंधित जिले के संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए कार्यमुक्त करना होगा।

डीडवाना-कुचामन में सड़क हादसे रोकने के लिये “सेफ आई-सेफ हाइवे” अभियान शुरू

सड़क हादसों को रोकने की दिशा में एक अनोखा और सराहनीय कदम उठाया, हादसों पर लगाम लगेगी

डीडवाना, (निर्स)। कुचामन जिले में सड़क हादसों को रोकने की दिशा में एक अनोखा और सराहनीय कदम उठाया गया है। जिले में पहली बार “सेफ आई-सेफ हाइवे” अभियान की शुरुआत हुई है, जिसका शुभारंभ छापरी-दौलतपुरा टोल प्लाजा से राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने किया। इस मौके पर मंत्री चौधरी ने अभियान को सड़क हादसों में कमी लाने वाला प्रयास बताया और कहा कि यह केवल स्वास्थ्य शिविर नहीं, बल्कि जनजीवन को बचाने का मिशन है, जिसे वे पूरे प्रदेश में लागू करवाने के लिए सरकार से चर्चा करेंगे।

इस अभियान के तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के चालकों, खासकर ट्रकों के चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चालकों की आंखों की रोशनी, बीपी, शुगर और बीएमआई की जांच की गई और जिनकी नजर कमजोर पाई गई, उन्हें मौके पर ही निःशुल्क चश्मे दिए गए। ब्लड प्रेशर या शुगर की समस्या सामने आने पर उन्हें



अभियान के तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों की जांच कर निःशुल्क चश्मे दिए।

फौरन दवाईयां और परामर्श भी दिया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड्गावत ने बताया कि अभियान के पहले ही दिन 300 से ज्यादा चालकों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिनमें से कई

को चश्मे और दवाईयां दी गईं। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न टोल प्लाजा पर अब हर महीने तीन शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें चिकित्सा, पुलिस और परिवहन विभाग को संयुक्त भागीदारी

रहेगी। उनका कहना है कि इस अभियान के जरिए, सड़क हादसों में 25 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने भी अभियान को सड़क

■ यह अभियान केवल स्वास्थ्य शिविर नहीं, बल्कि जनजीवन को बचाने का मिशन है, जिसे पूरे प्रदेश में लागू करवाने के लिए सरकार से चर्चा करेंगे : राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी

■ अभियान का शुभारंभ छापरी-दौलतपुरा टोल प्लाजा से राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने किया

सुरक्षा की बड़ी पहल बताया। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस और प्रशासन सड़क हादसों को रोकने के लिए एक विस्तृत योजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें ब्लैक स्पाट्स पहचानने, अन्य कमियां दूर करने और ऐसे स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन भी शामिल है। स्वास्थ्य परीक्षण करवाने पहुंचे ट्रक चालक भी इस पहल से बेहद संतुष्ट नजर आए। पंजसत के हरजिंदर सिंह ने कहा कि व्यवसाय के चलते वह कभी अपना स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवा पाते थे, लेकिन इस शिविर में उन्हें पता चला कि उनका बीपी हाई है और नजर

जर्जर स्कूल भवन की छत ढही

उदयपुर, (निर्स)। जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके कोटड़ा के महाड़ी बंवरिया फला सांकरा की उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत बुधवार को अचानक ढह गई। हादसा सुबह छह बजे हुआ उस समय स्कूल में शिक्षक और छात्र कोई भी नहीं थे इस कारण कोई नुक़ान नहीं हुआ। सूचना पर उपखण्ड अधिकारी हंसमुख कुमार मौके पर पहुंचे और जेसीबी कीमदद से मलबा हटवाकर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पास स्थित दूसरे भवन में स्कूल का संचालन शुरू करवाया। शिक्षकों के अनुसार गत दो वर्षों से भवन की हालत खस्ता है, जिसकी सूचना उच्चस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे चुके हैं। शिक्षक अरविन्द के अनुसार स्कूल भवन की जर्जर हालत के कारण नामांकन 225 से घटकर 190 हो गया है। यह स्कूल 2021-22 में क्रमोन्नत हुआ तब से अतिरिक्त कमरे की भी मांग कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं होने से जर्जर भवन में बने दो कक्ष में ही स्कूल चलाना पड़ रहा है।

कुराबड ब्लॉक में लैपर्ड का आतंक

उदयपुर, (निर्स)। जिले के कुराबड ब्लॉक में आतंक का पर्याय बने लेपर्ड ने मंगलवार रात में दो अलग-अलग गांवों में तीन श्वानों को अपना शिकार कर ग्रामीणों को और भयभीत कर दिया है। पहली घटना ग्राम पंचायत गुडली के काली मगरी गांव की है। जहां ग्रामीण भेरुनाथ के घर के बाहर बैठे पालतू श्वान को लेपर्ड ने अपना शिकार बना लिया। दूसरी घटना बोरी ग्राम पंचायत के आछट गांव की है जहां लेपर्ड ने दो श्वानों को अपना निवाला बना लिया। श्वानों के विल्लाने की आवाज सुन कर ग्रामीणों ने जाकर देखा तो लेपर्ड तेजी से भागता दिखा।

विद्युत केबल चोरी का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

पावटा, (निर्स)। बोरवेल की विद्युत कबिल चोरी में शामिल दो आरोपियों को विराटनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी की घटना का पर्दाफाश किया है।

पुलिस अधीक्षक जिला कोटपुतली बहरोड़ देवेन्द्र विसनोई ने बताया कि वर्तमान में पुलिस मुख्यालय द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए वॉलेंट अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली वैभव शर्मा के निर्देशन व वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर शिप्रा राजावत के सुपरविजन एवं विराटनगर थाना प्रभारी सोहनलाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा मुल्जिमां की गहनता से तलाश करते हुए काटन स्थल के आवसपा व संभावित स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। वहीं पुलिस की तकनीकी प्रणाली की सहायता से बदमाशान की तलाश की

■ अज्ञात चोर बोरवेल की करीब 1900 फीट विद्युत केबल काटकर ले गए थे

जाकर चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए प्रकाश उर्फ कालूराम पुत्र जयराम निवासी ढाणी कोल्हावाली तन बिशानगढ़ थाना मनोहरपुर, राजू उर्फ भूरिया पुत्र बल्लू उर्फ फकीरिया निवासी तिराहा माजिका बाग अचरोल थाना चंदवाजी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों से पूछताछ जारी है। विराटनगर थाना प्रभारी सोहनलाल ने बताया कि एक अगस्त को परिवारी लालाराम सैनी पुत्र रामसहाय सैनी ढाणी चैनाकी तन मैड ने मामला दर्ज करवाया था कि अज्ञात चोर बोरवेल की करीब 1900 फीट विद्युत केबिल को काटकर चोरी कर ले गए। जिस पर मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

खेतों पर लगी विद्युत केबल चोरी

भीलवाड़ा, (निर्स)। जिले के मांडल थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं से आमजन में भय दिखाई दे रहा है। वहीं पीड़ित परिवारों में रोष है। मंगलवार रात को चौर क्षेत्र के भीमड़ियास गांव में आधा दर्जन से अधिक खेतों पर लगे विद्युत केबल को काटकर फरार हो गए। सुबह जब किसान खेत पर पहुंचे तो किसानों के खेतों पर लगी टयूबवेल की केबल और कुओं पर लगी विपुल केबल कटी हुई मिली। इस पर अन्य ग्रामीणों को घटना के बारे में अवगत कराया। सभी ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहले भी कई बार चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। लगातार चोरी की घटनाओं के कारण लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। पीड़ितों में गांव के ही गोपाल बलाई, पनालाल बलाई, शंकलाल बलाई, सोहन बलाई, कैलाश कामड, भैरू लोहार सहित कई किसानों के यहां पर खेतों में चोरी की घटनाएं हुई हैं।

कार्यालय नगर पालिका, इन्द्रगढ़ जिला बुन्दी (राज.)

क्रमांक : न.पा.ई. / 2025-26 / 1778

निर्नांक : 04.08.2025

NOTICE INVITING BIDS

Bid for Nagar Palika Indragarh of Procurement are Invited from Interested Bidders Up to 11.00 AM , 04.08.2025 To 20.08.2025. Other particulars of the Bid Army be Visited on the Procurement Portal (<http://sppp.raj.nic.in>) or (www.gem.gov.in) of the State, and local self Departmental Website.

NIB Code :- DLB2526A4329

UBN :- 1. DLB2526SLRC13716

2. DLB2526SLRC13717

अध्यक्ष

नगर पालिका इन्द्रगढ़

राज.संवाद / सी / 25 / 7666

अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका इन्द्रगढ़

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DN GHATOL DISTT BANSWARA (RAJ.)

No. 312

Date: 25.07.2025

Notice Inviting Bid No. 02/2025-26

NIB- PWD2526A2221

Bids for Rate Contract of Road Repair and Maintenance Works are invited from interested bidder's upto 19.08.2025, 05.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://www.eproc.rajjasthan.gov.in> and <http://www.sppp.rajjasthan.gov.in>) of the state. The approximate value of procurement is rs. 215.00 Lacs.

UBN- PWD2526WSOB08033, TO PWD2526WSOB08038

(Naresh Shersya)

Executive Engineer

PWD Division Ghatol

Distt. Banswara

DIPRC/10830/2025

MBM UNIVERSITY, JODHPUR

Advertisement No. :- MBMU/DFPEA/ADVT/2025/15

Dated :- 31/07/2025

Admission Notice - 2025-2026

Ph. D, P.G., B. Plan and ADCGC Course

Applications are invited from eligible candidates for admission Ph. D, P.G., B. Plan and Advance Diploma in Child Guidance and Counselling Course in MBM University, Jodhpur. Interested candidates should apply online on the MBM University website on or before 11 August, 2025, and deposit the application fee online. It is essential to submit the hard copy of their application forms along with proof of application fee and all requisite documents on or before 05:00 PM, 18 August 2025 in the respective Department of the MBM University, Jodhpur (Raj.). All further information will be given only on the University website <https://mbm.ac.in>, admission.mbmuni@mbm.ac.in.

Raj.Samwad/C/25/7616

Registrar, MBM University, Jodhpur

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RAJASTHAN STATE HIGHWAYS AUTHORITY, JAIPUR

No.Raj Kaj No. 16935834

Date: 04.08.2025

NIT NO. 23/2025-26

NOTICE INVITING BID

Bids for "Routing maintenance of Ajeetgarh-Chala section of SH-13, Sikar-Ganeri Jaisangwarh section of SH-20 & 20A, Bidisar-Nakha section of SH-20 and Singhana-Buhana-Haryabhar border Section of SH-133 (total length: 233.955 Km.) are invited from interested bidders upto 11.30 AM on 11.08.2025. The date of opening of bids if 11.08.2025 at 12.00 PM.

Other particulars of bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajjasthan.gov.in>, <https://sppp.rajjasthan.gov.in>) of the state. The estimated value of aforementioned work is Rs. 192.60 Lakh.

UBN NO. PWD2526WSOB0825

(Akshay Kumar Jain)

Member (C & PPP),

RSHA, Jaipur

DIPRC/11067/2025

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर

111, वल्लभ नगर, उदयपुर (राज.) फ़ोन 313001 फ़ैक्स 0294-241571, E-mail: directorrcert@rajasthan.gov.in

क्रमांक - सर्वोच्च अग्र-उच्च/उच्च/2025-26/1173

दिनांक - 05/08/2025

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि RSCERT, उदयपुर द्वारा अनुपयोगी /अप्रचलित /नकारा सामग्री जिनकी Book Value IT Equipments/Electronics Rs. 3017786 एवं Non IT Equipments - Furniture etc. Rs. 175964 है की सार्वजनिक नीलामी जहाँ है जैसी स्थिति में है उस आधार पर निर्नांक 29.08.2025 को प्रातः 11.30 बजे से कार्यालय के परिसर में की जावेगी। नीलामी योग्य सामग्री का अवलोकन एवं नीलामी की अन्य शर्तें कार्यालय समय में कार्यालय में देखी जा सकती है।

निदेशक

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर

रज.संवाद/सी/75/7662

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

Tel No. 1462-258665, 257509 Email Add: npsbawar@gmail.com

क्रमांक / निर्माण / 2025-26 / 5958

दिनांक- 04.08.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 08/2025-26

नगर परिषद, ब्यावर द्वारा परिषद क्षेत्र में SFC, FFC एवं परिषद कोष के अन्तर्गत निर्माकित निर्माण कार्य करवाया जाने हेतु परिषद के सम्बन्धित श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारी से E-Procurement प्रक्रिया के तहत केवल www.eproc.rajjasthan.gov.in की ऑनलाईन निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 20/08/2025 साय 06:00 बजे तक निविदा भरी जा सकती है एवं ई-निविदा फॉर्म शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि नगर परिषद के Axis Bank के खाता संख्या 914010005810609 आई.एफ.सी. कोड UTIB0001825 में जमा कराकर बोली धरोहर का डी. डी./बैंकर चेक नगर परिषद, ब्यावर के निर्माण शाखा में दिनांक 21/08/2025 को प्रातः 11 बजे से पूर्व जमा करवाना अनिवार्य कराना अनिवार्य है। कुल 04 निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 31.67 लाख रुपये है। ई-निविदा सूचना की समस्त शर्तें SPPPP पोर्टल पर देखी जा सकती है।

जिसका NIB Code DLB2526A4329 है एवं UBN नम्बर निम्नानुसार है:-

(i) DLB2526WSOB13676 (ii) DLB2526WSOB13678 (iii) DLB2526WSOB13680 (iv) DLB2526WSOB13681

आयुक्त

प्रशासक

राज.संवाद / सी / 25 / 7652

नगर परिषद, ब्यावर

नगर परिषद, ब्यावर

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद

(राज्यीय) विश्व प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली, कोटा, Website : www.kotamc.org, Email : nksouth@gmail.com

क्रमांक - प. 4/1)टीपीएनए/संसाधन/2025/287

दिनांक - 28/05/2025

संशोधित बिड सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी बिड सूचना संख्या-240 दिनांक 18.07.2025 UBN No.- RGA2526SLRC00114 में बिड प्रपत्र की Technical Bid Data Sheet के बिन्दु संख्या-6 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1. A Self Declaration for not being black listed by any Procuring entity if Debarred by the State Government and Rajasthan Gramin Ajiwika vikas Parishad. Department During the last 3 years with seal & Sign of Authorised Signatory.

उक्त के अतिरिक्त बिड प्रस्तुत करने, कार्यालय में डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने एवं बिड खोलने की दिनांक भी निम्नानुसार संशोधित की जाती है :-

क्र.सं.

Activity

संशोधित दिनांक

समय

1

Last Date & Time for Submission for Bid

13.08.2025

11:30 AM

2

Last Date & Time for Submit Physical Demand Draft (DD)

13.08.2025

12:00 PM

3

Date & Time of Technical Bid Opening

13.08.2025

12:30 PM

राज.संवाद/सी/25/7643

जिला परियोजना प्रबंधक, राजीविका, जयपुर

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

राजीव चौक ब्रह्मा, रावत रोड, सीटीएच कॉम्प्लेक्स, कोटा, Website : www.kotamc.org, Email : nksouth@gmail.com

क्रमांक - न.निको/रजि./निगम/2025/567-581

दिनांक - 29/07/2025

Notice inviting request for proposal (RFP) : 2025-26

नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से नगर निगम कोटा दक्षिण में कन्सलटेन्ट/पेनल के गठन हेतु कुल निम्न कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। संवेदक निविदा प्रपत्र नगर निगम कोटा दक्षिण की वेबसाइट <http://kotamcsouth.org.com>, <http://www.urban.rajjasthan.gov.in/anks>, <http://sppp.raj.nic.in>, <http://eproc.rajjasthan.gov.in>, से प्राप्त कर सकेंगे।

निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाइट से)

01.08.2025 से 14.08.2025 तक

निविदा की धरोहर राशि, निविदा शुल्क व प्रोसेसिंग

01.08.2025 से 14.08.2025 तक

शुल्क व तकनीकी बिड के दस्तावेज ऑन-लाईन अपलोड करने की तिथि

07.08.2025 (प्रातः 11:00 बजे)

प्री-बिड मीटिंग की तिथि

18.08.2025 (प्रातः 11:00 बजे)

निविदा खोलने की तिथि

क्र.सं.

कार्य का नाम

धरोहर राशि

निविदा शुल्क

फीस

समयावधि

1

Preparation of DPR & BoQ including architecture and structural and design services with details planning. (i) Commercial Complex/ Other Building/ Facad Development/ Parks/ Land Scapina/ Beautification Projects.

25000/-

1500/-

500/-

12 माह

2

Preparation of DPR & BoQ including architecture and structural and design services with details planning. (ii) Chouraha Geo-Metrical Desig/ Sports Grounds/ Roads/ Small Bridge.

25000/-

1500/-

500/-

12 माह

3

Preparation of DPR & BoQ including architecture and structural and design services with details planning. (i) Community/ Shamsaahn/ Toilets

25000/-

1500/-

500/-

12 माह

4

Preparation of 3D Model of proposed schemes/ Building/ Chauraha etc. (ii) Computer Generated Model/ 3D View (All Sides)/ Walk Through.

25000/-

1500/-

500/-

12 माह

राज.संवाद/सी/25/7678

अधीक्षक अभियंता

नगर निगम कोटा दक्षिण

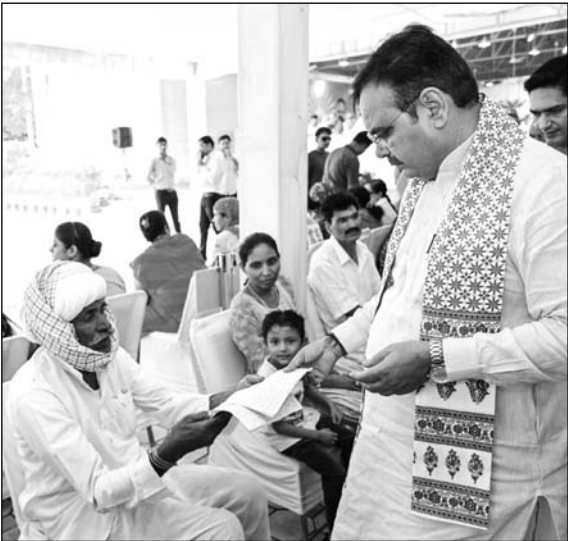
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से जनसुनवाई बनी सुशासन की नई मिसाल

मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सभी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। शासन की सेवा का माध्यम मानते हुए यह सरकार

- जयराम और कैलाश को मिला कृषि विद्युत कनेक्शन
- मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद, अब नहीं सूख रही फसलें

प्रदेशवासियों के हित के लिए पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं संवेदनशीलता के साथ पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा नियमित रूप से की जा रही जनसुनवाई भी इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम है।



मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई में समस्या का समाधान किया।

जनसुनवाई में फरियादी नगर निगम, जेडीए, गृह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,

जल संसाधन सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। कोई परिवारी बीमारी में इलाज की मदद के लिए आते हैं तो कोई परिवारी अपनी पेंशन से जुड़े प्रकरण

को निस्तारण के लिए तो कोई विद्युत कृषि कनेक्शन के लिए। मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सभी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर रहे हैं जिससे आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

कोटपूतली के नारायणपुर तहसील निवासी जयराम किसान परिवार से हैं। उन्होंने कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था जोकि पिछले काफी समय से लंबित था। जनसुनवाई में अपने इस प्रकरण को लेकर जब जयराम आए तो मुख्यमंत्री ने फसलों के सीजन को देखते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। अधिकारियों ने जयराम के कृषि कनेक्शन आवेदन को प्राथमिकता से लेते हुए कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। इसी तरह अलवर की लक्ष्मणगढ़ तहसील के कैलाश चंद मीणा को भी कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में फसलों की सिंचाई नहीं होने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने जनसुनवाई में मुख्यमंत्री को अपनी इस परेशानी से अवगत कराया।

कुमावत को एड-हॉक कमेटी का कंवीनर बनाने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड-हॉक कमेटी के क-वीनर के तौर पर दीनदयाल कुमावत की नियुक्ति करने पर सहकारिता रजिस्ट्रार, आरसीए और दीनदयाल कुमावत को नोटिस जारी कर 19 अगस्त तक जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सवार माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक

27 जून को दीनदयाल कुमावत को आरसीए की एड-हॉक कमेटी का क-वीनर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। एड-हॉक कमेटी का कंवीनर वह व्यक्ति ही बन सकता है, जो आरसीए चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो। दीन दयाल कुमावत का सवाई माधोपुर से कोई रिश्ता ही नहीं है। वे ना तो सवाई माधोपुर में जन्मे और ना ही वहां निवास करते हैं। वे सवाई माधोपुर

के किसी प्राइमरी क्रिकेट क्लब के पदाधिकारी भी नहीं हैं। ऐसे में वे जिला संघ के किसी पद के लिए भी पात्र नहीं हैं। इसके बावजूद भी उन्हें एड-हॉक कमेटी का कंवीनर बनाया गया है। इसलिए उनके नियुक्ति आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों और दीनदयाल कुमावत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

भारतीय नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों के हितों को सुरक्षित करे सरकार

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को कहा है कि वह भारतीय नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों के हितों को सुरक्षित करने के लिए कानून की समीक्षा करे और जरूरत पड़ने पर उन्हें संशोधित करने पर विचार करे। अदालत ने कहा कि ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे को मजबूत करने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ऐसे अनूठी परिस्थिति में बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश सेहर गंगिया के अपने पिता के जरिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि इमिग्रेशन ब्यूरो याचिकाकर्ता की मां की एनओसी के बिना उसकी वीजा अवधि अधिकतम समय के लिए बढ़ाई। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता ब्यूरो में ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निवासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

याचिका में कहा गया कि उसके माता-पिता का मार्च, 2018 में विवाह हुआ था। इसके बाद वे आस्ट्रेलिया गए थे। जहां 1 जून, 2020 को याचिकाकर्ता का जन्म हुआ। इस पर वहां की सरकार ने नवंबर, 2021 में

- अदालत ने कहा कि इमिग्रेशन ब्यूरो याचिकाकर्ता की मां की एनओसी के बिना उसकी वीजा अवधि अधिकतम समय के लिए बढ़ाई। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता ब्यूरो में ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निवासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता
- याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निवासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

याचिकाकर्ता को नागरिकता दे दी। इसके बाद वह भारत सरकार से वीजा लेकर अपने माता-पिता के साथ यहां आ गईं। इस दौरान उसकी समय-समय पर वीजा अवधि 24 जनवरी, 2024 तक बढ़ाई गई। याचिका में कहा गया कि इस बीच याचिकाकर्ता के माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद पैदा हो गया और उसकी मां ने याचिकाकर्ता के पिता पर कई केस कर दिए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से इमिग्रेशन ब्यूरो में याचिकाकर्ता की वीजा अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया, जिसे ब्यूरो ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसकी मां ने वीजा अवधि बढ़ाने के लिए एनओसी नहीं दी। ऐसे में याचिकाकर्ता को आशंका है कि उसे अवैध प्रवासी मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की

जाएगी। इसलिए मामले में कोर्ट दखल देकर उसकी वीजा अवधि बढ़ाए। इसका विरोध करते हुए इमिग्रेशन ब्यूरो की ओर से अपी तह कोवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी विभाग याचिकाकर्ता के खिलाफ कई दंडात्मक कार्रवाई या उसे डिपोर्ट नहीं कर रहा है। ब्यूरो की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ऑस्ट्रेलिया की नागरिक है और उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाए।

शिक्षा के साथ संस्कारों की सीख दे रहा है गायत्री परिवार: दिलावर

जयपुर। किरण पथ, मानसरोवर स्थित गायत्री वेदना निवारण केंद्र परिसर में मां भगवती उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रवेशोत्सव- 2025 बुधवार को मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर थे। उन्होंने मां गायत्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर दिलावर ने कहा कि गायत्री परिवार के इस विद्यालय ने बहुत कम समय में अच्छी तरक्की की है। यह विद्यालय शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार भी प्रदान कर रहा है। यह बहुत खुशी की बात है कि विद्यालय का शुभारंभ मेरे द्वारा हुआ था तथा आज प्रवेश उत्सव भी मेरी उपस्थिति में हो रहा है। विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार सामाजिक एवं राष्ट्रहित के कामों में सदा अग्रणी रहता है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि गायत्री परिवार सदैव समाज एवं राष्ट्र के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजकीय विद्यालय में बड़ी तेजी से नामांकन में वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए गुणात्मक प्रयास एवं नवाचारों का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। बच्चों ने गायत्री मंत्र के उच्चारण के



गायत्री परिवार के मां भगवती विद्यालय के नव प्रवेशित छात्रों का प्रवेश उत्सव मनाया।

साथ शिक्षा मंत्री का आत्मीय स्वागत किया। शिक्षा मंत्री एवं अन्य अतिथियों ने बच्चों को स्कूल बैग, स्टेशनरी सहित अन्य आवश्यक सामग्री भी वितरित की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी एवं राजस्थान जोन समन्वयक ओमप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि यह विद्यालय गायत्री परिवार द्वारा नि:शुल्क संचालित किया जा रहा है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय में

- देवनानी की बिरला से संसदीय विधायी मामलों पर चर्चा

किये जाने का अनुरोध किया। बिरला ने संबंधित अधिकारियों को राजस्थान विधान सभा के नेवा प्रोजेक्ट की कठिनाइयों को दूर करने के निर्देश दिए। बिरला ने देवनानी को नेवा प्रोजेक्ट के संबंध में लोकसभा से हर सम्भव सहयोग के लिए आश्चस्त किया।

देवनानी ने बिरला को राजस्थान विधान सभा परिसर में बनाई गई कारगिल शौर्य वाटिका की जानकारी दी।

देवनानी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस पर राजस्थान विधान सभा में कारगिल शौर्य वाटिका में वीरगंगाओं द्वारा चौधारोपण किया गया। बिरला ने राष्ट्र के शौर्य के लिए विधान सभा द्वारा किये गये इस नये कदम की सराहना की। 75 वर्षों के गौरवशाली डिजिटल म्यूजियम को प्रतिदिन लोग देखने आ रहे हैं प्रतिदिन आमजन बड़ी संख्या में देखने आते हैं। उन्होंने इतिहास को रेखांकित करते हुए निकट भविष्य में आयोजित होने वाले विधानसभा से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी बिरला से साझा की।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवनानी पर राजस्थान प्रदेश में विद्युत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

- जैसलमेर के फूसासर में 765 के.वी. में स्थापित होगा विद्युत उपकेन्द्र

सरकार द्वारा बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्राथमिकता से निर्णय लिए जा रहे हैं।

इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने जैसलमेर जिले की भगियाणा तहसील के फूसासर में 765 के.वी. के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा यह विद्युत उपकेन्द्र 80 हैक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का यह निर्णय पश्चिमी राजस्थान सहित पूरे प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस उपकेन्द्र की स्थापना से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा आमजन को सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

नवोदय विद्यालयों में सुरक्षा व स्टाफिंग में खामियों को लेकर नोटिस जारी

आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच 147 छात्रों ने आत्महत्या की थी

जयपुर/जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पी.एस. भाटी और न्यायमूर्ति संदीप तनेजा शामिल हैं, ने देशभर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में सुरक्षा, स्टाफिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर खामियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार,

शिक्षा मंत्रालय और नवोदय विद्यालय समिति को नोटिस जारी किया है। यह याचिका अधिवक्ता विनीत आर. दवे द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कई नवोदय विद्यालयों में अब तक पूर्णकालिक वार्डन, काउंसलर, सीसीटीवी निगरानी, परिधि सुरक्षा, आपात प्रबंधन और शिकायत निवारण तंत्र जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं। जबकि शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई, एनसीपीसीआर, एनडीएमए द्वारा इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कई चौंकाने वाले तथ्य को उजागर

- जवाहर नवोदय विद्यालय में 6800 से भी अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं
- विद्यालयों में साफ सफाई, सुरक्षा, टुटे-फुटे आधारभूत ढांचे और अन्य कई तरह की मानसिक परेशानीयो से छात्रों को झुझना पड़ता है

किया है जैसे कि दिसम्बर 2024 की शिक्षा के क्षेत्र में संसद की खासी समिति को भी उद्धृत किया है जिसके अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय में 6800 से भी अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद खाली पड़े है। यानी इन विद्यालयों में 24.77 प्रतिशत पदो की रिक्तियों को भरा नहीं गया है जबकि कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि रिक्तियों को जल्द भरा जाये। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 2019 में जारी एक परिपत्र के माध्यम से सफाई कर्मचारियों और चौकीदारों को

एमटीएस के रूप में छात्रावासों की देखरेख के लिए नियुक्त करने का निर्देश दिया गया, जो केवल औपचारिकता रह गया है और योग्यता आधारित स्टाफिंग के मापदंडों का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त, याचिका में यह भी जोर दिया गया है कि विगत वर्षों में नवोदय विद्यालयों में आत्महत्याओं सहित कई छात्र मौतों की घटनाएं सामने आई हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी और छात्रावासों में अपर्याप्त निगरानी की ओर इशारा करती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि आरटीआई से प्राप्त जानकारी के

अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच 147 छात्रों ने आत्महत्या की थी। आरटीआई से ही प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 से 2017 के बिच ही इन विद्यालयों में 49 छात्रो ने आत्महत्या की, जिसमें से आधे एसएसी -एसटी वर्ग के थे। वही 2019 से 2023 के बीच 25 छात्रो ने आत्महत्या की, जिसमें भी एक बड़ा हिस्सा एसएसी -एसटी वर्ग का था। याचिकाकर्ता का कहना है कि ज्यादातर इन मौतों में कई मामलों में एफआईआर दर्ज है परन्तु कई मामलों में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि इन विद्यालयों में साफ सफाई, सुरक्षा, टुटे-फुटे आधारभूत ढांचे और अन्य कई तरह की मानसिक परेशानीयो से छात्रों को झुझना पड़ता है, और आये दिन इन मुद्दो पर प्रदर्शन किये जाते हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं।

विवाद बढ़ा तो ठेकेदारों ने 20 प्रतिशत रेट घटाकर ले लिया पौधे सप्लाई का टैंडर

- कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। ग्रेटर निगम में पौधे सप्लाई के टैंडर में भारी गड़बड़झाला चल रहा है। "वन टाइम प्लान्टेशन" के लिए 10 फ़ीट पौधे देने के लिए ठेकेदारों ने पहले तो मात्र 5 प्रतिशत कम रेट डाली थी, परन्तु हैरिटेज निगम में 55 प्रतिशत कम दर आने के बाद जब विवाद बढ़ा तो इन्ही फर्मों ने अपनी रेट 20 प्रतिशत तक घटाकर काम ले लिया।

अब चर्चाएं यह हो रही हैं कि आखिर हैरिटेज निगम से 35 फ़ीसदी ज्यादा कीमत पर पौधे खरीदने के लिए ग्रेटर निगम के अफसर उत्सुक क्यों हैं? वह भी उस स्थिति में जब अधिकांश ठेके एक ही फर्म मैसर्स जसवाल बिल्डर्स के नाम पर छूटे हैं। हालाँकि उद्यान शाखा के अफसरों का कहना है कि 50 से 55 प्रतिशत कम राशि पर पौधे उपलब्ध

करवाना संभव ही नहीं है। परन्तु सवाल यह उठ रहा है कि यह चिंता को कम दर पर ठेके लेने वाले संवेदक को होनी चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक ग्रेटर निगम प्रशासन ने वन टाइम प्लान्टेशन कि निविदा के कार्यदेश "नेगोशिएशन" के बाद 20 प्रतिशत कम दर पर जारी किये हैं। यहाँ ठेकेदार ने 300 रुपए के 10 फीट के पेड़ 270 से 285 रुपए तक में देने की दर डाली थी, परन्तु जब हैरिटेज निगम में आधी कीमत यानी कि 135 से 150 रुपए तक की रेट आयी तो बड़ा विवाद हो गया। तमाम विवादों के बावजूद ग्रेटर निगम प्रशासन ने यह कार्यादेश जारी करने का फैसला लिया। मजदार बात यह है कि जेडीए प्रशासन ने भी इसी तरह ठेकेदारों से 160 से 170 रुपए के बीच खरीदे है। ऐसे में सवाल यह उठ रहे है कि आखिर

ग्रेटर निगम प्रशासन ही जानबूझकर लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान क्यों झेलने पर उतारू है। जबकि तीनों विभागों ने पौधों की एक समान खरीद दर 300 रुपए तय की थी। जिसमें नीम, शीशम, करंज, गुलमोहर, अमलतास, अशोक, चंपा, आवला, सीताफल, खेजड़ी, अर्जुन, बालम खेड़ा, कनेर, हरसिंगार, शहदतू, अमरूद, पीपल, जामुन, बेलपत्र, गुड़हल, मौलश्री, चंदन और आम के पेड़ शामिल हैं।

सूत्रों की माने तो ग्रेटर नगर निगम की उद्यान शाखा ने इस बार "वन टाइम प्लान्टेशन" के 30 लाख रुपए से कम के टैंडर में भी कुछ ऐसी शर्तें जोड़ दी थी, जिसके कारण "डी" श्रेणी के ठेकेदार चाहते हुए भी इसमें शामिल नहीं हो पाए। इस कारण इन निविदाओं में सिर्फ चुनिंदा फर्मों ने ही भाग लिया।

भाजपा रक्षाबंधन पर्व को सेवा, संगठन और समर्पण के रूप में मनाएगी

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी आगामी 8 से 10 अगस्त तक पूरे राजस्थान में रक्षाबंधन पर्व को जनसहभागिता, संगठनात्मक सहभागिता एवं सामाजिक समर्पण के साथ भव्य रूप में मनाने जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता "रक्षा का यह पर्व, सामाजिक एकता और सेवा का अवसर" के मूलभाव के साथ जिलों, विधानसभाओं और मंडलों में समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाएंगे।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और अभियान संयोजक मुकेश दाधीच ने बताया कि प्रत्येक जिले में एक जिला महामंत्री एवं महिला मोर्चा की दो पदाधिकारी संयोजक व सह प्रोजेक्ट के रूप में कार्यक्रम का संचालन करेंगे।

8 अगस्त को सम्मान व समर्पण दिवस:

इस दिन पार्टी कार्यकर्ता टैफिक पुलिस, अस्पताल स्टाफ, विद्यालयों, सरकारी व निजी कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों सहित सेवाभावी कर्मियों को राखी बांधकर आभार प्रकट करेंगे। बहनों द्वारा तिलक, राखी एवं मिष्ठान वितरण कर यह संदेश दिया जाएगा – आप हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं।

स्थानीय मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से इस सेवा भावना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

9 अगस्त को संगठनात्मक एकता

व परिवार दिवस पर भाजपा कार्यकर्ता इस दिन अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे और बुध, मंडल, शक्ति कैठ स्तर पर संगठन के सदस्यों के बीच भाईचारे का पर्व मनाकर भाजपा परिवार – एक सूत्र में बंधा, संकल्पित भारत के लिए समर्पित भाव का संशक्त करेंगे।

10 अगस्त को सेवा व सामाजिक सद्भाव दिवस को भाजपा कार्यकर्ता सीमाओं पर तैनात सैनिकों को राखी भेजेंगे या उनके साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। साथ ही कच्ची बस्तियां, मजदूर बस्तियां, झुग्गी-झोपडियों और घुमंरू समाज के बीच जाकर राखी व मिठाई वितरित की जाएगी। यह दिन "रक्षा का धागा, सम्मान और अपनत्व का संदेश" लेकर सेवा और संवेदना का उत्सव बनेगा।

यह आयोजन सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों व अन्य पदाधिकारियों की सहभागिता से जिले, विधानसभा एवं मंडल स्तर पर आयोजित होगा। पूर्व तैयारी बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं।

भाजपा का उद्देश्य रक्षाबंधन को सेवा, संगठन और समर्पण के पर्व के रूप में जन-जन तक पहुंचाना है।

रक्षा सूत्र से बंधेगा भारत, एकता, सेवा और संस्कारों के साथ – यही है इस कार्यक्रम की मूल भावना।

जयपुर स्मार्ट सिटी सीईओ डॉ. निधि पटेल ने की समीक्षा बैठक

जयपुर। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीईओ डॉ निधि पटेल ने बुधवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्मार्ट सिटी सीईओ डॉ निधि पटेल ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि स्मार्ट सिटी में बने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कैमरों से कचरा फैकने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए।

जिससे कि सड़क पर कचरा फैकने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीईओ निधि पटेल ने कहा कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि शहर के प्रमुख बाजारों में देर रात तक खुलने वाली दुकानों से कचरा सड़क पर ही फैका जा रहा है, जो कि सुबह तक सड़क पर ही पड़ा रहता है और ओपन डिपो का रूप लेकर शहर में सफाई व्यवस्था को खराब कर रहा है। इसलिए एग्रीगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी के अधिकारी मिलकर दोस प्लानिंग करें और उन दुकानों को चिह्नित कर समझाइश करें नहीं मानने पर भारी



जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीईओ डॉ. निधि पटेल ने बुधवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में समीक्षा बैठक की।

चालान वसूला जाए। जिससे कि सफाई व्यवस्था बेहतर हो।

वहीं समीक्षा बैठक के दौरान सीईओ निधि पटेल ने स्मार्ट सिटी के प्रगतिरत प्रोजेक्ट को समीक्षा की और कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही लाल ड्रंगरी कचरा ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण कार्य, एमआरएफ प्लॉट के शुरू होने के लिए शीघ्र पॉल्यूशन पनओसी लेने और लंगडियावास में पौधरोपण करने के निर्देश दिए।समीक्षा बैठक में स्मार्ट सिटी

के अधिकारी और नगर निगम हेरिटेज के जोन उपायुक्त और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बाजारों में कचरा संग्रहण के लिए चल रहे निगम के हूपर, व्यापारी हूपर में ही डालें कचरा वहाँ, सीईओ डॉ निधि पटेल ने कहा कि नगर निगम हेरिटेज की ओर से समयानुकूल सभी बाजारों में हूपर चल रहे हैं। दुकानदार अपने कचरे को हूपर में ही डालें, सड़क पर कचरा नहीं फैलाए, जिससे कि सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो।

सिराज ने हाल के दिनों में बहुत सुधार किया है : मोईन अली

लंदन, 6 अगस्ता। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोईन अली ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ संपन्न सीरीज में भारत के मोहम्मद सिराज के शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की और कहा कि इस गेंदबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक संपूर्ण गेंदबाज बनने की दिशा में बड़ी प्रगति की है। प्रमुख प्रॉपर्टी डेवलपर जीएफएस डेवलपमेंट्स के लंदन कार्यालय के हालिया दौर के दौरान मोईन अली ने कहा, सिराज ने इंग्लैंड सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। गेंद के साथ उनकी ऊर्जा, आक्रामकता और निरंतरता विचस्त्रीय है। वह भारत के लिए एक सच्चे मैच विजेता के रूप में परिपक्व हुए हैं और बल्लेबाजों के लिए उनका सामना करना हमेशा एक चुनौती होती है। उन्होंने कहा, मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात गेंद पर नियंत्रण रखने की उनकी क्षमता है। उनका दिल बड़ा है और वे कभी पीछे नहीं हटते - यही उन्हें इतना खास बनाता है। उनके द्वारा डाले जा रहे प्रभाव का श्रेय उन्हें जाता है, अली, जो वर्तमान में दुबई में रहते हैं और जीएफएस कार्यालय में अपनी यात्रा के दौरान वहाँ की संपत्तियों के बारे में पृथताछ कर रहे थे। मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ सभी पांच टेस्ट मैच खेले और कोई भी मैच नहीं छोड़ा। उन्होंने पांच टेस्ट मैचों में 23 विकेट लेकर श्रृंखला का अंर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में किया। मोईन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और दुबई में अपनी क्रिकेट क्षताओं को तलाश रहे हैं, जहां वे अब रहते हैं और इस शहर को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक मानते हैं। सीएफएस डेवलपमेंट्स के सीईओ इरफान वाहिद ने कहा, मोईन एक बेहतरीन क्रिकेटर थे और उन्होंने हाल ही में हुए डब्ल्यूसीएल टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था। हमारे लंदन कार्यालय में मोईन अली का स्वागत करते हुए हमें खुशी हुई। वह न केवल एक विचस्त्रीय खिलाड़ी हैं, बल्कि एक विचारशील व्यक्ति भी हैं। हम उन्हें उनकी पसंद और मूल्यों के अनुरूप संपत्ति खोजने में मदद करने के लिए उत्साहित हैं। मोईन अली हाल ही में संपन्न वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स में इंग्लैंड चैंपियंस के लिए खेले थे और आगामी टी20 टूर्नामेंट में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखना चाहेंगे।

आरसीए करौली जिला अंडर-19 इंरपुर शील्ड टीम की ओपन चयन ट्रायल 8 को

जयपुर, 6 अगस्ता। आरसीए के तत्वाधान में आयोजित होने वाली आगामी राज्य स्तरीय अंडर 19 इंगपुर क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाली करौली जिला क्रिकेट संघ टीम के चयन हेतु आरसीए द्वारा चयन ट्रायल आगामी 8 अगस्त को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित आरसीए अकादमी पर 10 बजे आयोजन किया जायेगा। राजस्थान क्रिकेट संघ एडहॉक कमेटी संयोजक डी डी कुमावत के अनुसार चयन ट्रायल में को ही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जिनका जन्म दिनांक 1/9/2006 या उसके पश्चात हो। चयन ट्रायल में भाग लेने हेतु खिलाड़ियों को निम्नलिखित मूल दस्तावेज साथ लाना आवश्यक है :- कंप्यूटर जनित जन्म प्रमाण पत्र (अनिवार्य), मूल प्रमाण पत्र (अनिवार्य), पिछले तीन वर्षों की शिक्षा की अंकतालिका (अनिवार्य), आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/पैन कार्ड।

जयपुर जिले की सीनियर गर्ल्स फुटबॉल टीम के चयन हेतु ट्रायल

जयपुर, 6 अगस्ता। राजस्थान फुटबाल संघ और भीलवाड़ा जिला फुटबाल संघ के तत्वाधान में राजस्थान राज्य सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता भीलवाड़ा में 16 से 18 अगस्त के मध्य आयोजित की जा रही है। इसमें भाग लेने वाली जयपुर जिले की टीम के चयन हेतु ट्रायल का आयोजन आगामी 10 अगस्त, रविवार को एसएमएस स्कूल के फुटबॉल ठाांड, रामबाग सफ़िल, जयपुर में आयोजित की जा रही है। यह ट्रायल राजस्थान फुटबाल संघ के द्वारा गठित जयपुर जिला फुटबॉल संचालन समिति के द्वारा आयोजित की जा रही है। संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य अब्दुल जब्बार ने बताया कि जयपुर जिले की टीम को इस ट्रायल के लिए वह महिला खिलाड़ी जिनके आधार कार्ड जयपुर जिले का है यानी कि वह जयपुर जिले के निवासी है वही पात्र है। सभी इच्छुक खिलाड़ियों को रविवार 10 अगस्त को सुबह 7 बजे तक एसएमएस स्कूल के फुटबॉल ठाांड पर ट्रायल हेतु रिपोर्ट करनी है। ट्रायल में भाग लेने हेतु सभी इच्छुक खिलाड़ियों को 9 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।

हाइजिया वेंचर्स ने अपनी टीम के लिए सानिया मिर्जा को बनाया ब्रांड एंबेसडर

नई दिल्ली, 6 अगस्ता। गौरव अग्रवाल की कनाडा समर्थित निवेश फर्म हाइजिया वेंचर्स ने टेनिस प्रीमियर लीग (टीपीएल) के सातवें सीजन से पहले गुरुराम ग्रैंड स्लैमस टीम को खरीदने के साथ ही दिग्विज स्टाार सानिया मिर्जा को टीम का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। टीपीएल भारत की चौथी ऐसी स्पोर्ट्स लीग बन गई है जो लगातार सातवें सीजन में पहुंची है। इसकी फास्ट-पेस्ड और दर्शकों को पसंद आने वाली प्रारूप की वजह से ये लीग लगातार निवेशकों और दर्शकों को आकर्षित कर रही है। गौरव अग्रवाल कहा, टेनिस और खेलों से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव है। एक पिता के तौर पर भी मैं युवा टेनिस खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहता हूं। यह निवेश खेल और फैंटाजी मैनेजमेंट में हमारे कदम को मजबूत करता है। सानिया मिर्जा ने कहा, मैं एक ऐसी टीम से जुड़कर खुश हूं जो टैलेंट और इनोवेशन दोनों को महत्व देती है।

गिल जुलाई महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए नामांकित

दुबई, 6 अगस्ता। भारत के कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को आईसीसी महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर के साथ, भारत के कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को पुरुष वर्ग में नामांकित किया गया है। इंग्लैंड की खिलाड़ी सोफिया डंकले और सोफी एक्लेस्टोन के साथ आयरलैंड की कप्तान गैबी लुईस भी महिला वर्ग में नामांकित हैं। इस दौरान गिल ने कुल 567 रन बनाए हैं, जिसमें बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बनाए गए 430 रन भी शामिल हैं, जो उन्हें इस दौड़ में शामिल करता है। वहीं स्टोक्स और मुल्डर ने भी शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया है। डंकले के बल्ले और एक्लेस्टोन के भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर किए गए प्रदर्शन ने उन्हें इस दौड़ में शामिल किया है, जबकि लुईस



का जिम्बाब्वे के खिलाफ दोनों प्रारूपों में बल्ले से अच्छा प्रदर्शन उन्हें इस दौड़ में शामिल करता है। एक स्वतंत्र आईसीसी वोटिंग अकादमी और दुनिया भर के प्रशंसकों को अब विजेताओं का फैसला करने के लिए वोट देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।



फुटबॉल कोच ने एसएमएस स्टेडियम में पत्रकार के साथ की धक्का-मुक्की

जयपुर, 6 अगस्ता। फुटबॉल खिलाड़ियों के हाथों में फावड़े देकर फुटबाल ग्रांड्स को ठीक करा रहे कोच को देखा तो रिपोर्टर फोटो खींचने लगा तभी पाट टाइम कोच नीत कमल ने पत्रकार के साथ धक्का मुक्की कर मोबाइल छीनने की कोशिश की। जब रिपोर्टर ने इसका विरोध किया तो कोच नीत कमल कहने लगा कि स्पोर्ट्स कॉर्डिसिल के अधिकारियों ने फुटबॉल खिलाड़ियों को ही फुटबाल ग्रांड्स ठीक करने को कहा है। ये कहकर फुटबाल कोच नीत कमल ने सभी खिलाड़ियों से वापस फावड़े फेंकने को कहा। खिलाड़ियों से फुटबाल ग्रांड्स को ठीक कराना कहां तक जायज़ है ये तो खेल परिषद सचिव राजेन्द्र सिंह सिसौदिया और नीरज पवन ही बता सकते हैं।

भारतीय एथलीट विश्व खेल 2025 के पांच खेलों की 23 पदक स्पर्धाओं में लेंगे हिस्सा

चेंगदू (चीन), 6 अगस्ता। भारतीय एथलीटों की 17 सदस्यीय टीम आज से शुरू हो रहे विश्व खेल 2025 के 12वें संस्करण की पांच खेलों की 23 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगी। इस बार विश्व खेलों में 34 खेलों और 60 विधाओं में 253 पदक स्पर्धाएं होंगी। पॉवरबोटिंग और चीयरलीडिंग को पहली बार इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। भारत इनमें से कुल पांच खेलों तीरंदाजी, बिलियर्ड्स, रैकेटबॉल, रोलर स्पोर्ट्स या स्केटिंग और वुशु में 23 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लेगा। भारत के तीरंदाजी दल में अभिषेक वर्मा और परनीत कौर, स्पीडस्केटर वेलकुमार आनंद कुमार और आर्यनपाल सिंह घुमन, तथा वुशु एथलीट नाओरेम रोशबिना देवी, मधुरा धमनागांवकर शामिल हैं। भारत मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में भी भाग लेगा, जो कि लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 में भी शामिल होगी।

राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन की घटिया निर्माण कार्य की वजह से ही हमने लेजेंजी टी-10 लीग के आयोजकों को साउथ पवेलियन की इजाजत नहीं दी गई

दोबारा से फोर्सिलिंग नई लगाकर साउथ पवेलियन की दीवारों की कमी को छुपाया नहीं जा सकता : नीरज के. पवन



प्रबंधन द्वारा इस पूरे मामले में जिस तरह की लापरवाही की गई है उस निर्माण कार्य को जब तक सुरक्षित रूप में नहीं किया जाएगा तब तक कार्य समाप्त नहीं माना जाएगा। स्टेडियम में साउथ ब्लॉक पहली बारिश ही नहीं झेल पाया है। जिससे सरकार के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए है। ग्रांड्स प्लेयर पर बने हॉल और दोनों ड्रेसिंग रूम में ड्रिफ्टिंग के माध्यम से पानी फर्श पर भर रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर बने हॉल की फॉल सीलिंग गिर चुकी है। उस पर लगी सभी लाइट्स लटक गई है। वुडन फ्लोरींग भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जयपुर में डोमेस्टिक टूर्नामेंट के



अलावा प्राइवेट टूर्नामेंट आयोजित किये जाएंगे अगर ऐसी स्थिति में किसी टूर्नामेंट का आयोजन होता है तो खिलाड़ियों और उनके साथ आए मेहमानों, दर्शकों की जान मुश्किल में आ सकती है। कोई भी दुर्घटना साउथ पवेलियन में कभी भी होने की

संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ दुबारा से फोर्सिलिंग नए लगा कर का आयोजन की दीवारों को कमी को छुपाया नहीं जा सकता। राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन की घटिया निर्माण कार्य की वजह से ही हमने लेजेंजी

हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है : मैकुलम

लंदन, 6 अगस्ता। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम का कहना है कि उन्होंने उन क्षेत्रों की पहचान कर ली है जहां इंग्लैंड को एंशेज से पहले सुधार करना होगा, जब भारत के खिलाफ एक रोमांचक सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई और मुख्य कोच का मानना ​​है कि पांचवें टेस्ट में भारतीय टीम जीत की हकदार थी। भारत ने इस एंडरसन-तेंदुलकर टॉफी सीरीज के 25वें और आखिरी दिन 56 मिनट के शानदार खेल में 2-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए छह रन की जीत हासिल की, जो रनों के लिहाज से उनकी सबसे कम अंतर की जीत थी। मैकुलम ने कहा, इस टेस्ट में भारत जिस तरह से अंत तक खेला, मोहम्मद सिराज में अपने 30वें ओवर में 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए एक शेर का दिल दिखाया, जो उनके पांचवें टेस्ट मैच में एक अविश्वसनीय प्रयास था। इंग्लैंड अब सितंबर में दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के खिलाफ सफ़ेद गेंद की सीरीज में उतरेगा, इसलिए खिलाड़ियों के पास आराम करने का समय है। साल की शुरुआत से ही कोच के रूप में मैकुलम दोनों चुनौतियों में शामिल रहेंगे। मैकुलम ने कहा, हम पहले सब कुछ शांत होने देंगे और हम यह पता लगाएंगे कि क्या अच्छा रहा है और फिर यह तय करना शुरू करेंगे कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं, ताकि जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचें, तो हमारे पास एक बड़ा मौका हो। हम जानते हैं कि हमारे पास सुधार की कुछ गुंजाइश है। यह एक प्रतिस्पर्धी सीरीज रही है, जिसमें, कुछ खिलाड़ी चोटिल भी हुए। यह सीरीज ड्रां हो चुकी है।



पूर्व काउंटी कोच यौन दुराचार के आरोप में निलंबित

लंदन, 6 अगस्ता। एक अज्ञात पूर्व काउंटी क्रिकेट कोच को यौन दुराचार के आरोप स्वीकार करने के बाद नौ महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। स्वतंत्र क्रिकेट अश्लसन पैनल ने पाया कि उस व्यक्ति ने 2023 और 2024 की गर्मियों में स्टाफ की दो महिला जूनियर सदस्यों को यौन रूप से स्पष्ट तस्वीरें भेजी थीं। हमने पेशेवर आचरण नियमों के पांच उल्लंघनों को स्वीकार किया, जिसमें दो सहकर्मियों को अनचाही यौन तस्वीरें भेजना भी शामिल है। पैनल ने असाधारण स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों और नाम सार्वजनिक करने पर गंभीर नुकसान के खतरे के कारण व्यक्ति की पहचान बताने से इनकार कर दिया। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी महिला प्रतिवादी से बहुत छोटी थी और वह क्रिकेट क्लब में उससे कहीं अधिक वरिष्ठ पद पर था। उसके व्यवहार के कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया और तब से वह खेल में कार्यरत नहीं है। पैनल को दिए गए आवेदनों में, यह उल्लेख किया गया कि कोच ने अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी है और सच्चा पश्चाताप व्यक्त किया है। बीबीसी की एक खबर के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने स्वेच्छा से एक शिक्षा पाठ्यक्रम लिया था और अर्वांछित स्पष्ट संदेशों के प्रभाव के समझने के लिए एक पूर्व पेशेवर खिलाड़ी के साथ काम किया था। रिपोर्ट में कहा गया है, उन्हें उम्मीद थी कि अब वह एक बेहतर ईंसान बन रहे हैं। उन्हें कार्यस्थल की सीमाओं, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और यौन उत्पीड़न के बारे में बेहतर समझ थी। यह प्रतिबंध आरोपों के दर्ज होने से छह महीने पहले लगाया गया है, साथ ही तीन महीने का निलंबन और एक अनिवार्य शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। क्रिकेट नियामक के प्रबंध निदेशक क्रिस हावर्ड ने कहा: इस तरह का आचरण अस्वीकार्य है। जहां ऐसे मामले सामने आते हैं, उनकी जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

भारत की तनवी महिला वर्ग के सेमीफाइनल में यासिन पुरुष और नूर महिला वर्ग के सेमीफाइनल में



जयपुर, 6 अगस्ता। भारत की स्टार स्क्वैश खिलाड़ी तनवी खन्ना ने बुधवार को यहां बड़ा उलट फेर करते हुए सवाई मानसिंह स्टेडियम के स्क्वैश कोर्ट्स पर खेली जा रही एचसीएल इंडिया टूर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। तनवी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मिश्र की दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी मेन्ना वालिद को पांच सेटों तक चले कड़े संघर्ष में 3-2 से पराजित कर दिया। भारतीय खिलाड़ी ने 54 मिनट तक चला यह मुकाबला 11-8, 8-11, 11-7, 10-12, 11-6 से जीता। सेमीफाइनल में तनवी खन्ना का मुकाबला मलेशिया की गोह जी झुआन से होगा।

आज का एक और बड़ा उलटफेर पुरुष वर्ग में दिखा जहां गैर वरीयता के मिश्र के सैफ रेफे ने मलेशिया के चौथी वरीयता के डेर्रेन प्रणास को पांच सेटों तक चले कड़े संघर्ष में 11-3, 5-11, 11-13, 11-2, 11-3 से हरा सेमी फाइनल में जगह बना

ली। ये मुकाबला 64 मिनट तक चला। पुरुष और महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त मिश्र के यासिन शोहदी नूर खफागी आसान जीत के साथ अंतिम चार में पहुंच गए। पुरुष वर्ग के क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड यासिन शोहदी ने जापान के नाओकी हयाशी को

बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जाएगा

नई दिल्ली, 6 अगस्ता। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के आरटीआई संबंधी प्रावधान में संशोधन किया है जिसके तहत केवल उन्हीं संस्थाओं को इसके दायरे में रखा गया है जो सरकारी अनुदान और सहायता पर निर्भर हैं और इससे बीसीसीआई को काफी राहत मिली होगी। बीसीसीआई अब भी आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में संशोधन किया है। इसके अनुसार, अब केवल उन्हीं खेल संगठनों को इसके दायरे में लाया गया है, जो सरकारी अनुदान और सहायता लेते हैं। बीसीसीआई खेल मंत्रालय से कोई अनुदान नहीं लेता है। हालांकि विभिन्न संगठन कई बार बीसीसीआई को आरटीआई (सूचना का अधिकार) के दायरे में लाने की मांग करते रहे हैं। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने 23 जुलाई को लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025 पेश किया था। इस बिल में खेलों के विकास के लिए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बोर्ड, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, नेशनल खेल इलेक्शन पैनल और नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाने के प्रावधान हैं। पिछले

महीने लोकसभा में पेश बिल के क्लॉज 15(2) में कहा गया था कि किसी मान्यता प्राप्त खेल संगठन को इस अधिनियम के तहत अनेक कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों के प्रयोग के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक निर्भर हैं और इससे बीसीसीआई को काफी राहत मिली होगी। बीसीसीआई अब भी आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। खेल मंत्रालय से कोई अनुदान नहीं लेता है। हालांकि विभिन्न संगठन कई बार बीसीसीआई को आरटीआई (सूचना का अधिकार) के दायरे में लाने की मांग करते रहे हैं। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने 23 जुलाई को लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025 पेश किया था। इस बिल में खेलों के विकास के लिए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बोर्ड, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, नेशनल खेल इलेक्शन पैनल और नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाने के प्रावधान हैं। पिछले

राशिद खान की अगुवाई में अफगानिस्तान खेलेगा एशिया कप

काबुल, 6 अगस्ता। स्टार लेग स्पिनर राशिद खान की अगुवाई में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम आगामी एशिया कप में खेलेगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात में नौ से 28 सितंबर तक होने वाले एशिया कप के लिए 22 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। एसीबी की चयन समिति के सदस्य मीर मुबारिज ने बताया, राशिद खान अफगानिस्तान के सुपरस्टार हैं। उन्होंने हमेशा टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। फॉर्म में होना या खराब होना, यह खेल का हिस्सा है, लेकिन वह अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे मजबूती से वापसी करनी है और टीम और देश के लिए बड़े टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन करना है। मुबारिज ने कहा, हमने त्रिकोणीय सीरीज और एशिया कप से पहले तैयारी शिविर के लिए एक प्रारंभिक टीम की घोषणा कर दी है, जहां नए खिलाड़ियों की परख के माध्यम से स्टाफ और कप्तान, दोनों प्रशिक्षण और तैयारी शिविर के दौरान करेंगे। उन्होंने



कहा कि अगर चोटों के कारण उन्हें अपनी योजना में बदलाव नहीं करना पड़ा, तो वे प्रारंभिक शिविर के 22 सदस्यों में से ही अपनी विश्व कप टीम का चयन करेंगे।

उन्होंने टीम में शामिल तेज गेंदबाजों को लेकर कहा, हां , हम शायद आगामी एशिया कप में इन्हीं 22 खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे, लेकिन चोट लगने की स्थिति में बदलाव हो सकते हैं, और हम समय के साथ इन मुद्दों का ध्यान रखेंगे। हमने अब्दुल्ला अहमदजई, बशीर अहमद को टीम में शामिल किया है, और सलीम सफी भी चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। इसलिए, वे सभी 140 की रफ्तार से गेंदबाजी करने में सक्षम हैं।

उन्होंने कहा, पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान के पास राशिद खान, मुजीब, मोहम्मद नबी और अल्लाह अहमद गजनफर जैसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं। हमने नांग्याल खारोटी और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले शराफुद्दीन अशराफ को भी टीम में शामिल किया है

ऑजिव्यू के सहयोग द्वारा कोचेज सेमिनार में प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया

जयपुर, 6 अगस्ता। भारतीय तीरंदाजी संघ सहयोग से जयपुर में चल रही तीन दिवसीय कोचेज सेमिनार का आयोजन चल रहा है। यह सेमिनार जयपुर के एक प्रमुख होटल में आयोजित हो रहा है, जिसमें चयनित 45 प्रशिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। इस सेमिनार का उद्देश्य प्रशिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित करना और देश में तीरंदाजी की कोचिंग संरचना को सशक्त बनाना है। सेमिनार में आज ओजिव्यू के सचिन ने स्टैन्थ और कन्डीनसिंग की जानकारी दी। वहीं सभी कोचों को आज प्रैक्टिकल के साथ प्रशिक्षण दिया एवं नवीन वदलाव नियमों की जानकारी दी। साथ डोपिंग से खिलाड़ियों को वचाने की महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसमें राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ने आज सभी कोचों का स्वागत किया।



राज्य स्तरीय अंडर-19 वीमेन ट्रायल के पहले दिन राज्य की 450 खिलाड़ी पहुंचे

जयपुर, 6 अगस्ता। राजस्थान क्रिकेट संघ एडहॉक कमेटी संयोजक डी डी कुमावत के अनुसार राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आज से जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम स्थित अकादमी पर आयोजित की जा रहे 3 दिवसीय अंडर 19 वीमेन चयन ट्रायल के पहले दिन समस्त राज्य से लगभग 450 महिला खिलाड़ियों ने चयन ट्रायल में भाग लेने रजिस्ट्रेशन कराया। संयोजक के अनुसार आरसीए महिला चयन कमेटी ने आज चयन ट्रायल के पहले दिन लगभग 270 महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन व प्रतिभा को दौरान देखा। दल दिनांक 7 अगस्त को चयन ट्रायल के दूसरे दिन शेष महिला खिलाड़ियों की चयन ट्रायल होगी। आज सुबह आरसीए द्वारा आयोजित की

जा रही राज्य स्तरीय अंडर 19 वीमेन चयन ट्रायल के अवसर पर आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक डी डी कुमावत ने आरसीए अकादमी पहुंच कर राज्य की युवा महिला खिलाड़ियों की चयन ट्रायल की पूर्ण प्रक्रिया का निरीक्षण किया। साथ ही खिलाड़ियों से चर्चा करते हुए उन्हें आरसीए द्वारा हर स्तर पर उच्च स्तरीय पूर्ण पारदर्शी खेल वातावरण व सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रोत्सा दिया। इस दौरान संयोजक डी डी कुमावत ने राज्य के हर कोने से आयी हुई राज्य की युवा महिला खिलाड़ियों व उनके परिवजनों के लिए चयन ट्रायल के दौरान सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करने के लिए आरसीए स्टाफ को विशेष निर्देश भी दिए।

माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने के लिए डीपीआर बनेगी

सात हजार करोड़ रूपए की परियोजना से पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर की पेयजल समस्या का स्थाई निदान होगा

जयपुर, 6 अगस्त। पाली, जालोर, सिरोही बाड़मेर में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब मूर्त रूप लेगा। इस विषय को लेकर सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ एक अहम बैठक हुई। बैठक में सात हजार करोड़

- मुख्यमंत्री भजनलाल, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने परियोजना के बारे में विस्तार से ब्रीफ किया।
- वाफ़ोस ने परियोजना की इन्सपैक्शन रिपोर्ट जल संसाधन संभाग को सौंपी।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बुधवार को सुमेरपुर विधायक व कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने एक बैठक में माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाले सात हजार करोड़ रूपए के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा की।

परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए 15.60 करोड़ रूपए की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति जल संसाधान विभाग, जयपुर के मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। इस कार्य के लिए अधिशासी अभियंता, जल संसाधन खंड सलूंवर ने

वाफ़ोस लिमिटेड से अनुबंध कर कार्यदेश भी जारी कर दिए। इसके बाद वाफ़ोस द्वारा इन्सपेक्शन रिपोर्ट जल संसाधन संभाग, उदयपुर को प्रस्तुत किये जाने के बाद विभाग ने उसका अनुमोदन भी कर दिया है।

कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने

बताया कि सात हजार करोड़ रूपए का यह महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरा होने पर उदयपुर, सिरोही, पाली एवं जोधपुर जिले में पेयजल संबंधी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही, 16 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का पुर्नस्थापन होगा।

विपक्ष ने संसदीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उन झूठे दावों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है, जो संसद को सुचारु रूप से चलने से रोक रहे हैं।”

गोगोई ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि 1961 में राज्यसभा में चुनाव आचार संहिता के नियमों में संशोधन पर बहस हुई थी, उस चर्चा का नेतृत्व उस समय के कानून मंत्री गोपाल पण्डित ने किया था। गोगोई ने बताया कि 1981 में, कांग्रेस सांसद मनुभाई पटेल ने चुनावी कानूनों की समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस सांसद ने कहा, “1991 में, राज्यसभा में मौजूदा चुनावी कानूनों में संशोधन की तत्काल आवश्यकता पर बहस हुई। 2015 में, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने प्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) के लिए

प्रॉक्सी और ई-पोस्टल वोटिंग पर “कॉलिंग अटेंशन मोशन” प्रस्तुत किया था। कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने विपक्ष की राय को मानने की बात स्वीकार की।”

गोगोई ने कहा कि हाल ही में, 2019 में भी चुनावी सुधारों पर “अल्पकालिक चर्चा” हुई थी, जिसमें तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाग लिया था। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। सरकार को इस लंबे समय से लंबित और आवश्यक बहस में देरी नहीं करनी चाहिए।

गोगोई ने कहा, “आइए, संसद में चुनावी सुधारों पर चर्चा करें।” रमेश ने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि 1986 में भी व्यापक चुनावी सुधारों की आवश्यकता और संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करने पर चर्चा हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडू की “विद यू स्टालिन” योजना को हरी झंडी दी

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की “विद यू स्टालिन” योजना में वहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नाम के इस्तेमाल पर रोक वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को रद्द दिया।

इसके साथ ही अदालत ने सरकारी योजना के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले अन्नाद्रमुक सांसद सी.वी. धनमुगम पर अदालत का समय बर्बाद करने के एवज में 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति एन बी अंजारिया की पीठ ने उच्च न्यायालय का आदेश रद्द करते हुए, उसके खिलाफ राज्य सरकार और ट्रिविडु मुनेत्र कन्नगम (द्रमुक) पार्टी की अपील स्वीकार कर ली। पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा, हमने बार-बार कहा है कि राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए। अदालतों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक हिंसा-खिलाफ निपटारने के लिए किया जाना चाहिए। इस आदेश के साथ ही शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की विद यू स्टालिन योजना हरी झंडी दे दी।

‘अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए राज्य सरकारें चार हफ्ते में अधिसूचनाएं जारी करें’

- सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों को, कमजोर वर्गों को शिक्षा के लिए दिए गए 25 प्रतिशत कोटा में शामिल करने के निर्देश दिए

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और

उत्तरकाशी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के जगह-जगह अवरोध हो जाने के कारण अनेक वाहन अब भी रास्ते में फंसे हुए हैं। हर्षित स्थित सेना के कैंप में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिससे क्षेत्र में लॉजिस्टिक चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं। जैसे-जैसे खोज और बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है, स्थानीय अधिकारियों का मानना ​​है कि मृतकों के आँकड़े में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं और कई गांवों से संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। उत्तरकाशी इस समय हाल के वर्षों की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा की चपेट में है।

सीजेआई गवई का सीनियर वकीलों को अल्टीमेटम

नई दिल्ली, 06 अगस्त। चीफ जस्टिस ऑफ ​​इंडिया (सीजेआई) बी आर गवई ने बुधवार, 6 अगस्त 2025 को साफ ​​कर दिया कि 11 अगस्त से कोई भी सीनियर वकील उनकी अदालत में तत्काल सुनवाई के लिए मामले नहीं ला सकेगा। ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे जूनियर वकीलों को ऐसा करने का मौका मिल सके।

सीजेआई गवई ने वकीलों की ओर से तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई

- गवई ने कहा, 11 अगस्त से मेरे कोर्ट में कोई भी सीनियर वकील तत्काल सुनवाई के लिए केस नहीं ला सकेगा।

के लिए मामलों का मौखिक उल्लेख करने की प्रथा को दोबारा शुरू कर दिया था, जिसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बंद कर दिया था।

सीजेआई गवई ने कहा, “इस बात की पुर्खोर मांग उठ रही है कि सीनियर वकीलों को किसी भी मामले में तत्काल सुनवाई के लिए मेशन न किया जाए।”

उन्होंने अदालत के कर्मचारियों से कहा कि वे एक नोटिस जारी करें कि सोमवार से उनकी अदालत में किसी भी वरिष्ठ वकील को तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई के लिए मामलों का लाने की इजाजत नहीं होगी।

सीजेआई ने कहा सोमवार से किसी भी सीनियर वकील, किसी भी नामित सीनियर वकील को मामलों का उल्लेख करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जूनियर वकीलों को ऐसा करने का मौका दिया जाना चाहिए।

मैडिकल बोर्ड में 29 में से 24 लोक सेवक दिव्यांग कैटेगिरी के लिए अनफिट निकले

जयपुर, 6 अगस्त । एसओजी ने सरकारी नौकरी में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। एसओजी पुलिस अधीक्षक ज्ञान चंद ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से सूचना मिली कि विगत समय से विभिन्न सरकारी नौकरियों में अनेक चयनित उम्मीदवारों ने दिव्यांग नहीं होते हुए भी फर्जी तरीके से बनवाया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है।

सूचना मिलने के बाद एसओजी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मोणा के नेतृत्व में जांच दल गठित कर एसएमएस मैडिकल कॉलेज के विभिन्न विशेषज्ञों का बोर्ड गठित करवा कर दिव्यांग श्रेणी के लोक सेवकों की पुनः मैडिकल जांच करवाई गई, जिसमें 29 दिव्यांग लोक सेवकों की मैडिकल जांच कि रिपोर्ट प्राप्त की, जिसमें से मात्र 5 लोक सेवकों में दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना पाया

- एसओजी ने दिव्यांगत प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी पाने के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया।
- सबसे ज्यादा अनफिट कर्मचारी श्रव्य बाधित श्रेणी में पाए गए।

गया और बाकी 24 तथाकथित दिव्यांगों को मैडिकल बोर्ड ने दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट बताया। श्रव्यबाधित 13 में से 13 लोक सेवक दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट पाए गए। दृष्टिबाधित कथाकथित 8 दिव्यांग में से 6 दिव्यांग कैटेगरी के नहीं पाए गए। इसी तरह लोकोमोटर एवं अन्य प्रकार के 8 लोक सेवकों में से 5 दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट पाए गए।

अनफिट पाए गए लोक सेवक हैं- महेन्द्र पाल पुत्र गिरधारी सिंह, तहसील पुलिस थाना भीम राजसमंद; सवाई सिंह गुर्जर टिगरिया का पुरा, हिण्डीन, करौली; हन्टू गुर्जर चंदवाजी जयपुर; मनीष कुमार कटारा बरीली, रुपवास, भरतपुर; केशव उर्फ ​​खुब्बाराम रेनवाल; कविता रेनवाल; बिकेश कुमार नदबई; भरतपुर; भानुप्रताप कटारा, रुपवास; नफीस जुहरार, भरतपुर; रणजीत सिंह बयाना, भरतपुर; कलुआ राम बयाना भरतपुर; पवन कुमार आबूरोड सिरौही; विनोद कंवर आबू रोड सिरौही; दिनेश कुमार, धौरीमन्ना बाड़मेर; लोकेश नदबई भरतपुर; संजय नौखा बीकानेर; दीपू डीडवाना, कुचामन; गैंगू बलूपुरा पाली; प्रशांत सिंह गांधी नगर सिरौही; हिन्दूपाल सिंह केसरीसिंहपुरा गंगानगर; आसी कुमारी मारुडी, बाड़मेर; डॉ शंकर लाल मीणा देवपुरा बूंदी, गवादाश चौधरी रुपनगढ़ जिला अजमेर; किशोर सिंह सबलपुर डीडवाना कुचामना

एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक बयान में बताया कि 1 अक्टूबर से एयर इंडिया के सभी इंटरनेशनल फ्लाइटों की आवाजाही पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। मतलब कि एक अक्टूबर से प्रयर इंडिया के इंटरनेशनल विमानों की आवाजाही 12 जून से पहले वाली स्थिति में आ जाएगी।

अहमदाबाद हार्दसे के बाद एयर इंडिया के, इंटरनेशनल के साथ-साथ, घरेलू विमानों की उड़ानों पर भी असर पड़ा था। दुर्घटना के बाद, एयर इंडिया ने सुरक्षा जांच लॉन्च रहने तक अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आंशिक रूप से रोक दिया था।

समुद्री माल परिवहन बिबल पर संसद की मुहर

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। भारत से शेष दुनिया के समुद्री बंदगाहों तक माल ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों और अधिकार तथा छूट से संबंधित प्रावधानों वाले समुद्री माल परिवहन विधेयक के बुधवार को राज्य सभा ने विधेयक के हंगामे के बीच पारित कर दिया। इसके साथ ही, इस विधेयक पर संसद की मुहर लग गयी। इस विधेयक को लोक सभा ने गत 28 मार्च को पारित किया था।

राज्य सभा में आज शुद्धकाल के दौरान पहले स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे कार्यवाही पुनः शुरू होने पर विपक्ष

के हंगामे के बीच पीठासीन उपसभापति भुवनेश्वर कलिता की अनुमति से मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चल रहे मणिपुर के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित आय-व्यय का ब्यौरा रखा। हंगामे के बीच ही, विधायी कार्य के एजेंडा में पहले स्थान पर उल्लिखित समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पर चर्चा करायी गयी। इस विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के कतिपय संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज करने के बाद, विधेयक को बख्त मतदान से अनुमोदित कर दिया गया।

‘वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों का ब्यौरा शनिवार तक पेश करें’

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिए

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह विशेष पुनरीक्षण के दौरान बिहार मतदाता सूची से हटाये गए 65 लाख लोगों (मृत और स्थायी पलायन करने वाले) का विवरण शनिवार तक दे।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्स (एडीआर) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण की गुहार पर यह निर्देश दिया।

पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा, शनिवार तक जवाब दाखिल करें और भूषण को इसे देखने दें। फिर हम देख पाएंगे कि क्या खुलासा हुआ है और क्या नहीं।

पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी जाएगी।

इस पर चुनाव आयोग के

- चुनाव आयोग ने कहा कि राजनैतिक दलों को यह जानकारी दी गई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन दलों की लिस्ट मांगी जिन्हें यह जानकारी दी गई है।

अधिवक्ता ने कहा कि वह प्रस्तुत करेगा कि यह जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जानकारी साझा की गई है। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि वह अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखे।

पीठ ने निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता से कहा, उन राजनीतिक दलों की सूची दीजिए, जिन्हें यह जानकारी दी गई है। हम 12 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे। तब तक अपना (निर्वाचन आयोग का) जवाब दाखिल करें।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की जिताओं पर कहा, हम यह सुनिश्चित

करेंगे कि प्रभावित होने वाले प्रत्येक मतदाता को आवश्यक जानकारी मिले। एडीआर ने अपने आवेदन में कहा कि 25 जुलाई को निर्वाचन आयोग ने एक प्रेरित विज्ञापन जारी की, जिसमें कहा गया था कि लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

भूषण ने पीठ के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा, ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख नामों के छूटने की बात कही गई है, लेकिन इन नामों की कोई सूची नहीं दी गई। इसमें 32 लाख लोगों के पलायन की बात कही गई, लेकिन कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा, उन्हें (चुनाव आयोग) यह बताना चाहिए कि 65 लाख लोग कौन हैं? कौन पलायन कर गए हैं। कौन मर गए हैं? जाहिर है, बीएलओ ने उस व्यक्ति को हटाने या न हटाने की सिफारिश की है। भूषण ने दलील दी थी कि चुनाव आयोग ने दो निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। अन्य क्षेत्रों का क्या हुआ?

एस.सी.ओ. सम्मेलन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की आवश्यकता के साथ संतुलित करना, भारत-चीन संबंधों की परिपक्वता की परीक्षा होगी। भारत के लिए यह यात्रा चीन की पाकिस्तान नीति पर असंतोष जताने के साथ-साथ व्यापार, तकनीक और बहुध्रुवीय वैश्विक शासन पर साझा सोच तलाशने के लिए भी होगी।

मोदी की चीन यात्रा भारत की व्यापक विदेश नीति में एक पुनर्मूल्यांकन का प्रतीक है, जो एक ध्रुवीकृत होते जा रहे विश्व में एनर्जीतिक लचीलापन बनाए रखने की कोशिश को दर्शाता है। बाईशेंपटन, मॉस्को और बीजिंग के बीच यह संतुलन भारत की अगली कूटनीतिक दिशा को परिभाषित कर सकता है।

इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन में 10 सदस्य देशों के साथ बातचीत में आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दे शामिल रहने की संभावना है।

प्र.मंत्री ने कर्तव्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय होगा।

कर्तव्य भवन में पानी की ज़रूरतों के एक बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग की व्यवस्था की गयी है। यह भवन 30 प्रतिशत कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें इमारत को ठंडा रखने और बाहरी

शोर को कम करने के लिए विशेष कांच की खिड़कियां हैं। ऊर्जा-बचत करने वाली एलईडी लाइटें, ज़रूरत न होने पर लाइटें बंद करने वाले सेंसर, बिजली बचाने वाली स्मार्ट लिफ्टें और बिजली के उपयोग को प्रभावित करने की एक उन्नत प्रणाली हैं। कर्तव्य भवन-3 की छत पर लगे सौर पैनल हर साल 5 लाख 34 हजार यूनिट से ज्यादा बिजली पैदा करेंगे।